**2.00 P.M.**

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): (a) to (c) As per the One Stop Centre (OSC) Scheme guidelines, the Centre Administrator, the Case workers, the Para Medical Personnel, Counsellors and the multi-purpose workers are required to be females to ensure that OSCs are women-friendly.

To ensure quality at OSCs, training and capacity building initiatives have been undertaken at the national and State levels across the country and this is an ongoing process. A total number of 3544 OSC functionaries have been trained through various trainings and capacity building programmes so far.

---

## STATEMENT BY MINISTER CORRECTING ANSWER TO QUESTION

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन)**: प्रश्न काल का समय समाप्त हुआ। Now Statement correcting answer to question.

Statement to be made in the Rajya Sabha by the Hon'ble Minister of Law and Justice, correcting version of the statement/replies of the Hon'ble Minister to Supplementary to Rajya Sabha starred Question No. 115 during the discussions held in Rajya Sabha on 28.11.2019.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, I rise to make a statement correcting the answer given in the Rajya Sabha on the 28th November, 2019 to a supplementary question arising out of the answer to Starred Question No. 115 regarding ' India Justice Report 2019' .

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन)**: सदन की कार्यवाही दोपहर 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

*The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.*

---

*The House reassembled after lunch at one minute past two of the clock,*

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN) *in the Chair*]

## DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN): The Leader of the House.

**सभा के नेता (श्री थावरचन्द गहलोत):** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपसे और सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी बांध सुरक्षा विधेयक पर चर्चा कराना कार्य-सूची में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा प्रारम्भ करने की बजाय पहले MSME पर चर्चा प्रारम्भ करा दी जाए, तो उचित होगा। ...**(व्यवधान)**...

**श्री जावेद अली खान** (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आज लॉ मिनिस्ट्री पर चर्चा नहीं होगी और क्या सदन का समय 6.00 बजे तक रहेगा या 8.00 बजे तक? ...**(व्यवधान)**...

†**جناب جاوید علی خان:** مہودے، میں آپ کے مادھیم سے مانیئے منتری جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آج لأ منسٹری پر چرچہ نہیں ہوگی اور کیا سدن کا وقت 6.00 بجے تک رہیگا یا 8.00 بجے تک؟

**श्री थावरचन्द गहलोत** (मध्य प्रदेश): सायंकाल 6.00 बजे तक तो सदन चलेगा। उसके बाद जैसा माननीय सदस्यों का विचार होगा, उसके अनुसार काम होगा।

**श्री जावेद अली खान:** ठीक है महोदया, मैं यही जानना चाहता था।

†**جناب جاوید علی خان:** ٹھیک ہے مہودے، میں یہی جاننا چاہتا تھا۔

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Predesh): At what time are you going to take the Dam Safety Bill? Please inform us. आप बताइए आप उसे लेकर कब आएंगे? We came rushing.

SHRI BHUPENDER YADAV (Rajasthan): It will be decided by the Chair. We requested the Chair to first take up the discussion on MSME, and after that, whatever the Chair decide, we will do.

**श्री जयराम रमेश** (कर्नाटक): महोदया, इनका इरादा उस पर चर्चा कराने का नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री भूपेन्द्र यादव:** महोदया, मेरा निवेदन है कि पहले आप MSME को कार्य-सूची में ले लीजिए और उस पर चर्चा प्रारंभ कराइए तथा उसे समाप्त होने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन):** श्री श्वेत मलिक, कृपया आप अपना भाषण प्रारंभ कीजिए।

**श्री जयराम रमेश** (कर्नाटक): मैडम वाइस चेयरमैन, हमें मालूम है कि इनका इरादा उस पर चर्चा कराने का नहीं है।...**(व्यवधान)**...

†Transliteration in Urdu script.

**पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर):** उपसभाध्यक्ष महोदया, मेरा निवेदन है कि बात एकदम साफ है। कल MSME की चर्चा के लिए लगभग 24 माननीय सदस्यों के नाम आए थे। उनमें से कल 14 माननीय सदस्यों ने भाग लिया था और अभी भी 10 माननीय सदस्यों के नाम चर्चा करने हेतु शेष हैं। उनके भाषण होने और इस चर्चा का उत्तर, ये दोनों जरूरी हैं। इसलिए पहले इन्हें पूरा होने दीजिए...**(व्यवधान)**...

**श्री जयराम रमेश:** मैडम, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि इनका इरादा नहीं है।...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन):** ऐसा है कि मंत्री जी ने निवेदन किया है कि पहले MSME पर चर्चा कर ली जाए। इसलिए पहले हम इस चर्चा को पूरा कर लें, फिर उसके बाद उस पर ...**(व्यवधान)**... श्री श्वेत मलिक जी, कृपया आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

**श्री श्वेत मलिक** (पंजाब): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि micro, small and medium enterprises को जो सफलता मिली है, उसके लिए मैं ...**(व्यवधान)**...

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन):** कृपया आप बैठें। श्री श्वेत मलिक जी, आप अपना भाषण जारी रखें। ...**(व्यवधान)**...

**श्री श्वेत मलिक:** महोदया, आज जो MSME को सफलता मिली है, उसके लिए मैं हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे माननीय मंत्री, श्री नितिन जयराम गडकरी जी को बधाई दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो स्वर्णिम उपलब्धि प्राप्त हुई है, मैं आपको उसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि MSME देश का growth engine है। किसी भी देश की उन्नति का यह golden gate है, लेकिन हम से पहले कांग्रेस का जो लम्बा शासन चला, उस कांग्रेस को यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, लेकिन गरीबी हटाओ का निवारण नहीं किया। "गरीबी हटाओ" का निवारण किससे होना था? वह एमएसएमई जैसी योजनाओं से होना था, लेकिन "गरीबी हटाओ" का नारा सिर्फ नारा रह गया। कांग्रेस एक लंबे समय तक गरीब को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती रही और गरीब और गरीब होता रहा। हमने हमेशा यह सुना है कि गवर्नमेंट by the people, for the people होती है, पर वह जो गवर्नमेंट थी, वह by the people, for Congressmen थी। कांग्रेस का एमएसएमई सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं था, क्योंकि वह गवर्नमेंट by the people, for Congressmen थी। ...**(व्यवधान)**... वह निजी स्वार्थों पर थी। उसमें कहीं भी एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ नजर नहीं आई। मोदी जी, जिन्होंने एक स्वप्न लिया है कि 5 ट्रिलियन की economy बनानी है, जब उन्होंने संकल्प से सिद्धि तक एक नये भारत का निर्माण करने का संकल्प लिया था, तब सब लोग हंसते थे, लेकिन आज आप देखिए कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत में "जन-धन योजना" के अंतर्गत 32 करोड़ खाते खुल गए हैं, आज मोदी जी के नेतृत्व में 18 हज़ार गांवों में बिजली पहुंच गई है, आज

मोदी जी के नेतृत्व में घर-घर में गैस के मुफ्त चूल्हे पहुंच गए हैं। यह एक संकल्प होता है कि आज जो शौचालय बने हैं, उनका नतीजा यह हुआ है कि यह जो नया इतिहास बना है, जिसमें कांग्रेस को मुंह तोड़ पराजय मिली है और एक बार फिर मोदी जी का जो पूर्ण बहुमत के साथ शासन आया है, किसी सरकार को दशकों के बाद पहले से भी अधिक बहुमत मिला है, यह उनके इतने अच्छे कार्य करने के कारण था कि गरीब को पहली बार सरकार मिली। यह गरीब की सरकार थी।

महोदया, एमएसएमई, जिसके लिए मैंने पहले ही कहा है कि यह growth engine है, उसमें जो projection of jobs है, उसके अनुसार करीब 15 करोड़ जॉब्स एमएसएमई के माध्यम से मिलेंगी, क्योंकि जो maximum employment generation होता है, वह एमएसएमई के माध्यम से होता है। यह लघु उद्योग सेक्टर है।

महोदया, 50 परसेंट जीडीपी का जो एक प्रोजेक्टिड विज़न है, हमने जो यह सोचा है कि यह जीडीपी डबल डिज़िट में जाएगी, जीडीपी में जो 50 परसेंट contribution होगा, वह एमएसएमई के माध्यम से संभव होगा।

महोदया, मोदी जी ने हर भारतवासी को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि गरीबी को रोटी दे देंगे, तो वह फिर मांगेगा, लेकिन अगर किसी गरीब को आत्मनिर्भर बना देंगे, तो वह और लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाएगा और खुद भी आत्मनिर्भर होगा। यह मोदी जी की सोच है। एमएसएमई के माध्यम से मोदी जी ने जो प्रयास किए और उसमें जो नये-नये components introduce किए, वे इसीलिए हुए क्योंकि वह सही मायने में गरीब की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का लंबा शासन चला, लेकिन जो दलित थे, जो पिछड़े थे, जो गरीब थे, वे कोई ऑफिसर क्यों नहीं बन पाए? वे उद्योगपति क्यों नहीं बन पाए? उसका कारण यह था कि वोट बैंक के कारण ये चाहते ही नहीं थे कि वे लोग ऊपर उठें, ऊपर उठकर उनको भी ज्ञान हो और वे भी अपने ज्ञान से वोट डाल सकें। मोदी जी ने एमएसएमई सेक्टर में ये जो योजनाएं चलाई हैं, जैसे स्टार्ट-अप्स के लिए "मुद्रा बैंक" योजना है कि किसी भी वर्ग का जो एक intellectual बच्चा है, intelligent बच्चा है, वह केवल संसाधनों के कारण पीछे न रह जाए, इसके लिए "मुद्रा बैंक" योजना के माध्यम से अब बिना किसी collateral security के लोन मिलता है। उन्होंने यहां तक कर दिया है कि 1 करोड़ ₹ तक का लोन एक घंटे में मिलेगा। मोदी सरकार ने ऐसे इतिहास की रचना की है। इससे गरीब के बच्चे, जो स्टार्ट-अप्स थे, वे भी सामने आए और उद्योगपति बनने लगे। उनके लिए जो "स्किल इंडिया" की योजना थी - यह बड़ा कष्टदायक है कि आज भारत को आज़ाद हुए 70 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन आज भी जो "स्किल इंडिया" component है..। मैंने पहले भी सदन में बताया था कि यहां यूरोप में यह 80 प्रतिशत से अधिक है, नॉर्वे में 93 प्रतिशत लोग skilled हैं, लेकिन भारत में आजादी मिलने के लंबे समय के बाद भी 2.3 per cent skilled लोग हैं। अब जब व्यक्ति skilled ही नहीं होगा, तो

[श्री श्वेत मलिक]

efficiency क्या निकलेगी? मोदी जी ने पहली बार Ministry of Skill Development and Entrepreneurship बनाई और उसको लाखों-करोड़ का बजट दिया, जिससे यहां के जो गरीब हैं, हम उनको शिक्षित कर सकें, हम उनको skilled कर सकें और वे कहीं अधिक efficiency निकाल सकें। मैडम, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक लोहार काम करता है, वह जिस product का निर्माण करता है, अगर वह पुराने औजारों से निर्माण करेगा, तो दिन में पांच वस्तुएं बनाएगा, लेकिन अगर वह skilled होगा, modern machinery लेगा, उसके पास computerized machinery होगी, तो वही व्यक्ति 50 वस्तुएं बनाएगा। यह मोदी जी का स्वप्न है। Skill Development Ministry ने महिलाओं के क्षेत्र में, दलितों के क्षेत्र में, गरीबों के क्षेत्र में बहुत काम किया।

मैडम, मोदी जी ने आज SC/ST Hub योजना का निर्माण किया। मुझे बहुत दुख होता है कि जो हमारे दलित भाई हैं, या तो वे peon मिलेंगे या रिक्शेवाले मिलेंगे या रेहड़ी वाले मिलेंगे या मजदूर मिलेंगे। कांग्रेस के कुशासन के कारण उनको उद्योगपति नहीं बनने दिया गया। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आपके इतने लंबे शासन के बाद भी आज यह जो दलित वर्ग है, ये जो गरीब लोग हैं, ये उद्योगपति क्यों नहीं हैं? मोदी जी ने ऐसे वर्ग को उद्योगपति बनाने के लिए SC/ST Hub योजना शुरू की। साथ ही उन्होंने यह निश्चित किया कि जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे रेलवे है, Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL) है, इनको अपना 4 प्रतिशत जो material है, जो product है, वह जो दलित वर्ग का उद्योगपति है, उससे खरीदना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने marketing का इंतजाम भी साथ किया।

मैडम, इसके बाद 'Make in India' योजना है। यह आज तक सोचा ही नहीं गया। हमेशा विदेशियों के आगे झोलियां फैलाई गईं, चाहे वह डिफेंस हो, चाहे वह रेलवे हो, चाहे वह industry हो, हम पूरी तरह से विदेशियों के ऊपर निर्भर रहे और कितनी देशी पूंजी विदेशों में चली गई। जहां तक विदेशी मुद्रा की बात है, जहां आज ऐतिहासिक स्तर पर विदेशी मुद्रा का भंडार इकट्ठा हुआ है, जबकि हम कांग्रेस के राज में विदेशी मुद्रा के दिवालियेपन के कगार तक आ गए थे, क्योंकि सारी मुद्रा तो आयात करने में बाहर चली जाती थी। मोदी जी ने 'Make in India' योजना शुरू की कि यह जो हेलिकॉप्टर है, ये जो guns हैं, ये जो तोपें हैं, ...**(समय की घंटी)**... मुझे ज्यादा समय मिला है।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन)**: आपकी पार्टी के दो मेम्बर्स और हैं, आपको 10 मिनट समय मिला है।

**श्री श्वेत मलिक**: मुझे पंचारिया जी ने कहा है कि आप ज्यादा समय लीजिए।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन)**: आपकी पार्टी से आपको मिला कर तीन लोग हैं। आपको 10 मिनट समय मिला है।

**श्री श्वेत मलिक**: पंचारिया जी ने मुझे अधिक समय दिया है। पंचारिया जी आपको बता देंगे कि मुझे अधिक समय मिला है। मुझे पार्टी की तरफ से अधिक समय मिला है।

मैडम, आज उस स्तर के ऊपर आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। आज 'Make in India' है। आज डिफेंस का material यहां बन रहा है, आज रेलवे का material यहां बन रहा है, आज modern equipments, computers यहां बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि पहले मोबाइल की केवल दो factories थीं, लेकिन आज सौ से अधिक factories के साथ भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा mobile manufacturer बना है। यह मोदी सरकार की उपलब्धि है, जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए। अब ये जितनी योजनाएं बनी हैं, 'Make in India' भी बनी, ये Startups के लिए बनीं। ये सब MSME में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। सबसे पहले इनको credit की facility दी गई कि आपको लोन बिना किसी दिक्कत के मिलेगा और बड़ा लोन मिलेगा। एक करोड़ रुपए का लोन कोई छोटा लोन नहीं होता है। यह सब मोदी जी ने उपलब्ध करवाया है। आज आप देखिए कि मुद्रा बैंक के माध्यम से कितने ही गरीब घरों में दीपक जला है। Start-ups के माध्यम से इन गरीब लोगों को, इन नये-नये उद्योगपतियों को टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया गया है। क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कहा गया कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस रखी जाएगी। इसके बाद इन सबको बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया गया, क्योंकि कोई भी उद्योग इन्फ्रास्ट्रक्चर के बिना नहीं लग सकता है। हमारे गडकरी जी, जो सड़क परिवहन मंत्री भी हैं, उन्होंने नई सड़कें बनवाईं, नए फ्लाईओवर्स बनवाए, नये ओवरब्रिजेज़ बनवाए। हमारी सरकार ने गांव-गांव तक सड़क, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने के बाद अब गांव-गांव तक पानी देने की शपथ ली है। बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट मिलने से MSMEs काफी आगे बढ़ी हैं।

Testing facility and quality certification के लिए latest equipment उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि हर चीज़ की quality अच्छी बन सके। इसके साथ ही quality control marking की व्यवस्था भी की गई है, ताकि सभी quality control conscious बन सकें और हम विश्व बाज़ार के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकें, competition कर सकें और भारत की वस्तु विश्व में सबसे ऊंचे ब्रांड के तौर पर बिक सके। इन सब चीज़ों की व्यवस्था मोदी सरकार ने की है।

भारत में हर जगह 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई गई है। यह वही कांग्रेस सरकार थी, जिसके कारण 70 वर्षों तक 18,000 गांव बिना बिजली के रह गए, लेकिन पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार के माध्यम से घर-घर तक बिजली पहुंची है, गांव-गांव तक बिजली पहुंची है और गांव-गांव में इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। जो पावर है, वह MSMEs और industries की जननी है, इसलिए हमारी सरकार ने अधिकांश क्षेत्रों में 24 hours, 365 days पावर जेनरेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई है।

[श्री श्वेत मलिक]

Skill development का विषय मैंने पहले भी लिया था, मोदी सरकार ने महिलाओं, बच्चों, दलितों और गरीबों को शिक्षित करने का काम किया है, उनको तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा दी जा रही है, ताकि निश्चित होकर अपने साथ-साथ देश के विकास में भी वे अपना योगदान दे सकें और MSMEs के माध्यम से देश की जीडीपी और अधिक बढ़ सके।

Research and development के क्षेत्र में कितने ही IITs खोले जा रहे हैं, कितने ही IIMs खोले जा रहे हैं, कितने ही AIIMS खोले जा रहे हैं, कितनी ही Central Universities खुल रही हैं, यह सारा कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस के काल में यह सब एक स्वप्न की तरह था, लेकिन आज नए भारत का निर्माण हो रहा है। प्रधान मंत्री मोदी जी ने संकल्प से सिद्धि की बात कही है और कहा है कि मैं उस भारत का निर्माण करूंगा, जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जो आतंकवाद मुक्त होगा, जो पृथकतावाद मुक्त होगा, जो साम्राज्यवाद मुक्त होगा और जो गंदगी मुक्त होगा। ऐसे भारत के निर्माण में MSMEs का बहुत बड़ा रोल है।

इसके जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, जो कामगार हैं, उनके वैलफेयर के बारे में भी विशेष ध्यान रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के माध्यम से उनके लिए कई स्कीम्स आई हैं। पहली बार मज़दूरों को पेंशन देने वाली सरकार - मोदी सरकार है, पहली बार किसानों को पेंशन देने वाली सरकार - मोदी सरकार है, पहली बार छोटे व्यापारियों को पेंशन देने वाली सरकार - मोदी सरकार है। MSME के लोगों को marketing support दिया गया है। जो उत्पाद बन रहे हैं, मोदी सरकार उनको बेचने की व्यवस्था करती है। जो exhibitions लगती हैं, वहां इन लोगों को सरकार के द्वारा passes और रहने की सुविधा में subsidy दी जाती है। Cottage industry हमारी मुख्य इंडस्ट्री है। जो coir board industry है, उसको भी लाभ दिया गया है। ...**(समय की घंटी)**...

मैडम, अंत में मैं यह कहूंगा कि जो कांग्रेस का कुशासन रहा, जो mismanagement रहा, उसने गरीबों को बांट कर रखा, दबा कर रखा और इन गरीबों का उत्थान MSMEs के माध्यम से मोदी सरकार ने किया। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत आभारी हूं, धन्यवाद।

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Madam, before making my points, I would like to go back to early 20th Century, that is, 1907. In Bangiya Pradeshik Sammelan, Rabindranath Tagore was the President of that conference. A historic statement he delivered at that conference! Rabindranath Tagore was a very open-hearted person. He never said that we did not want heavy industries. In his statement he said very clearly that if we revive the country, then we require cottage

and small-scale industries; without having small-scale industries, India can't prosper. In his writings, he said very clearly, 'If we depended on the British, they would crush indigenous industries.' So, we shall have to put our full attention for the indigenous industries. Mahatma Gandhi also said that the rural industries are essential for the development of economy of the country.

The BJP is speaking on Khadi Gramodyog. It is Mahatma Gandhi who did a lot on it. It is he who said that without having gramodyog, without having *charkha,* Independence can't take place. So, if we want to set up *swadeshi bhavana,* it requires Swadeshi industries. But, nowadays, in the name of MSME, the present BJP Government is trying to destroy it. How are they destroying? Say, one MSME unit is producing one product. For that production, we don't have the market. Why do we not have the market? Because big industries are capturing all the markets. If you feel that you want to make arrangements for the survival of small-scale industries or MSMEs, then proper marketing arrangements have to be made by the State Governments and the Government of India. Unfortunately, you are doing nothing. On the contrary, what are you doing? You said that a bank can lend to the MSME a loan of ₹ 2 crore. Do you know what is happening? Particularly, your SBI is giving ₹ 50 lakh as a first instalment. After that, it says, 'You start the industry, we will further make investigation and only after that would we release the rest of the amount.' But, I know of so many cases in my State, in Jharkhand, Odisha and other States, where they have said that they would lend money, but actually they are not lending. As a result, what has happened? All these MSMEs have closed down. Howrah, near Kolkata, once upon a time was called Manchester of India. So many smallscale industries were there. They were manufacturing different types of components. All these components were used inside and outside the country. But, now, it looks deserted. The units are closed down because there is no market and nothing of that sort. You are claiming that you are removing *garibi of* the people. But, you are bringing the people into *garibi.* You are bringing them into *garibi* every inch and every time. Indiraji has said "गरीबी हटायेंगे", लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? गरीब को हटाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। गरीब को हटाने के लिए MSME बंद कर रहे हैं। You tell me, hon. Minister, you give me a reply. How many workers were unemployed due to the closing down of MSMEs? How many workers were in starvation situation in different parts of the country? Large sections of the people have no jobs because all these things are closed. To run the small scale industry, MSME, it requires supply

[Shri P. Bhattacharya]

**2.30 P.M.**

of raw materials. Who will supply the raw materials? Hon. Minister, you know it very well, unless and until you have a corporation to supply them the raw material, it is very difficult for them to purchase raw material. They could not get the raw materials. As a result, they cannot produce anything and they are suffering. I know it very clearly that large number of MSME industries, who were practically dependent on heavy industries to supply components, are not supplying the components because heavy industries are saying that some of the articles are now being manufactured by the contractors, by outsourcing and not by MSME industries in different parts of the country. Madam, if you go to Mumbai, you can see it. I visited many MSMEs. They said, we are not getting components from the heavy industries because they said we are doing all these things, perhaps outsourcing. All these things are happening. ...*(Time-bell-rings)*... So, I think, if you are serious about doing something for the MSME —I am not going into the GST —I can tell you, without having any market arrangements, banking support etc. in our country, MSME cannot survive under any circumstances. Micro, small and medium enterprise sector has emerged as a highly vibrant, dynamic sector of our Indian economy over the last five decades, but now the declining stage has started coming. The Government is saying, it is going up. Practically it is not going up. Don't depend on the papers. I know some of the leaders who will supply us the data saying that it has been increased. Practically, it is not. If you go to Howrah, you will see the condition there. You go to the suburb of Mumbai and see. You go to the suburb of Delhi, you will see what is happening there. MSME is in a very precarious condition. If the Government will not give proper attention to this, then, very shortly you will see that India will be a place where we don't have MSMEs. Before summing up, I would like to say a very pertinent thing.

The vibrant and dynamic sector —MSME —of our economy is not only playing a crucial role over the last five decades in providing a large number of employment opportunities at comparatively low capital cost than the large industries but also helping industrialization of rural and backward areas. There are so many districts in our country which are backward. If we do not give employment to these backward areas, how can you subsist it, I don' t know.

Madam, mechanisation has been introduced in the agriculture sector. The result

is: A large section of agriculture labour is out of land. They are looking at MSME. If this sector is not there, how will they survive? I don' t know.

On the basis of this, my humble submission to this Ministry is to kindly come up with a new Commission, have proper survey and take necessary steps so that MSME sector survives. Thank you.

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन):** सुश्री दोला सेन जी। दोला सेन जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि अपनी बात शुरू करने से पहले आपने जो ब्लैक टैग लगा रखा है, कृपया उसे हटा दें।

**सुश्री दोला सेन** (पश्चिमी बंगाल): मैडम, यह तो मेरा ornament है।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन):** नहीं, नहीं, आप उसको हटा दें। कृपया इस सदन की गरिमा बनाए रखें।

**सुश्री दोला सेन:** हम तो ornament पहनते हैं और यह ornament है।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन):** आपकी बात ठीक है, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ है। कृपया आप सहयोग करें और सदन की गरिमा बनाए रखें।

**सुश्री दोला सेन:** मैडम, क्या इससे सदन की गरिमा भंग हो रही है? I am not arguing with you Madam Vice-Chairperson. It is, ' No NRC, No CAA.' It is my ornament. If the Chair says that it is mandatory, then, okay. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN): Thank you.

MS. DOLA SEN (West Bengal): Madam Vice-Chairperson, today, you have allowed discussion on the Working of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

A few days ago, you were very kind to allow a discussion on the Working of the Ministry of Railway as well. The discussion was initiated by the leader of my party, the All India Trinamool Congress.

We asked seven questions to the hon. Railway Minister. We got a speech, but no answers! So, today, Madam, I request the hon. Minister, in his reply, to please answer the questions which Members are asking.

And, from last July, 2019, Session till date, several times, almost in every Session, our party has been asking different definite questions regarding disinvestment of public

[Ms. Dola Sen]

sector undertakings, public enterprises, corporatization of Defence sector, 100 per cent FDI in coal sector and non-payment of wages and salaries for the last ten months to the contract employees of BSNL and permanent employees of the Hindustan Paper Corporation. In these cases also, we have not got any answer. Today, again, Madam, I request the hon. Minister and the policy-makers of the Central Government to please answer our questions, so that the people of India may get their answers.

To understand the working of the Ministry of MSME, we have to understand what action hurt the MSME sector so much, who is responsible and why is it so? It is the hon. Prime Minister himself who is responsible. Sorry to say; but, it is the truth, because it was he who announced demonetization in November, 2016, which was a big blunder.

Now, I come to the second blunder which hurt the MSMEs. Madam, in July, 2017, the Goods and Services Tax was introduced in the country. We had supported the move, but strongly opposed on how it was implemented. The faulty implementation of the GST and faulty policy of demonetization resulted in a loss of ₹ 4.75 lakh crore to the country' s economy. But, you don' t want to take advice. You think you can do it all yourself. You don' t need anybody' s advice. And, you are insulting Parliament. Sorry, Madam. The Lok Sabha and the Rajya Sabha are in Session and, instead of addressing Parliament and the nation, you are avoiding Parliament and addressing the country through TV!

Now, let me not give a theoretical lecture on how progress has been made and come to the practical scenario. Madam, the MSME sector in Bengal is flourishing. West Bengal is a leading State in the MSME sector. As per the NSS Report of the Central Government, the State has 89 lakh MSME establishments. During the last eight years, the number of MSME clusters, in operation in Bengal, has grown. How has it grown? It has grown from 49 to 539! That' s why we say *'Banglar Gorbo Mamata',* which means "Bengal' s Pride is Mamata" . Bengal' s pride is also MSME; Bengal' s pride is also the agriculture; Bengal' s pride is also the organic farming; Bengal' s pride is also the social security for the *Kisan Khet Mazdoor Vargdaar;* Bengal' s pride is also *Samajik Mukti Prakalp* for the unorganized workers; Bengal' s pride is also *Joy Bangla* for the SCs, ST and the senior citizens; Bengal' s pride is also *Konya Shree;* Bengal' s

pride is also *Utkarsh Bangla*. And, obviously, Bengal' s pride is Mamata, *Banglar Gorbo Mamata.*

Rupees 2.4 lakh crore have been invested in SMEs through cooperative and commercial banks in my State.

The infrastructure for small industries has also seen tremendous growth. At present, fifty-two MSME Parks are operating; thirty-nine more such MSME Parks are under construction in my State. For further attracting MSME investment in the State, one hundred new MSME Parks are being established in the next three years.

The quantum of bank credit is a good parameter to judge how a State is doing in the MSME sector. The more the banks give to MSMEs, the better the State is doing. In the last two years, the growth of bank credit has been unprecedented. In 2018-19, it was ₹ 57,000 crores. This is almost 30 per cent higher than the credit in 2017-18.

Yes, West Bengal is India' s number one State in MSME. I am proud to tell you that in 2019-20, the credit flow to this sector already reached ₹ 35,000 crores, during the first two quarters of 2019. This meant a huge jump of 75 per cent on a year-on-year basis for the same period, last year. We are proud of this achievement. The Bengal Government has also introduced a new incentive scheme for the MSME sector, named *'Banglashree'*, which starts next month.

The State is taking all these initiatives even though the Centre owes the State of West Bengal about ₹ 50,000 crore. The Centre also owes the State thousands of crores on account of GST. The Centre also owes the State of West Bengal thousand and thousand crores on every other public and Government scheme.

This Government has got MSMEs into trouble. Please allow me one minute to tell you about this Government' s *'Becho India'* programme. They are selling everything, including the LIC, the BPCL, the Shipping Corporation of India, the Container Corporation of India, the Indian Railways, the Air India, the ECL, the Bridge and Roof, the Bengal Chemicals, the Indian Oil Corporation, the Chitharanjan Locomotive Works, the Alloy Steel Plants, etc., etc. At least, after this COVID-19, and the great job done by the Air India, I appeal to them not to sell the pride of the nation, the Air India. The Air India has stood by the nation in this crisis. We salute the Air India family

[Ms. Dola Sen]

and we must not sell this national treasure as well as the other public sectors also, which are also the national treasures. And we must not sell them.

Now, I come to the issue of financial crisis in the MSME sector. Only 15 per cent of the MSMEs in India receive formal credit. More than eighty per cent of them are under-financed or financed through informal sources. The World Bank estimates the credit gap of India' s MSMEs to be at around 25 lakh crore rupees. If the sector is not financed effectively, how will it empower the industry to grow? We need to bridge the credit gap urgently to ensure that the MSMEs are well-funded and their operations are not at stake due to lack of funds.

My next point is with regard to delay in repayments. A low demand, non-payment by customers, and banks not restructuring loans of MSMEs is affecting the sector. It is to be noted that repayments have been delayed by more than a month, sometimes up to four months. Banks are tagging such loans as Non-Performing Assets, as mandated. If this happens, then, it becomes difficult for the MSMEs to access further funds. The Government has to consider this and ensure that proper checks are in place which empowers the MSMEs to grow and not remain in the red.

Again, financials are the key fuel which allows the nourishment of the MSMEs. There has to be no impediments to access finance, as also policy intervention is required to make sure that the MSMEs are paid by their customers on time for them to service their loans as well. Also, leeway provisions have to be strengthened for MSMEs so that they do not suffer should they fail to pay their loans back in time.

My fourth point is about the negative credit growth. The credit growth for the MSME sector is muted. According to data from the Reserve Bank of India, for the micro and small segment, the credit growth has been negative, at -3.4 per cent, between April-November, 2019. For medium enterprises, it was negative, at -3.6 per cent. On a year-on-year basis too, credit growth till November 2019, in both micro and small as well as medium enterprises, has been negative, at -0.1 per cent and -2.4 per cent respectively.

My fifth point is about huge quantity of loans being restructured. In January, 2019, the RBI had allowed a one-time restructuring of existing MSME loans that have

defaulted but were not non-performing as on January 1. The original deadline of 31st March, 2020, was extended by a year, to 31st March, 2021, in the recent Union Budget. According to banks, MSME loans of about two trillion rupees were identified to be restructured by 31st March, 2020. Banks hope to meet, at least, 70 per cent of this target. Why is the MSME sector suffering when a majority of the loans have to be restructured? The Government has to find the root cause of this and ensure that such organisations do not grapple with the issues that are making it difficult for them to run.

My sixth point is that the budgetary allocation is not enough. The budgetary allocation for the MSME sector increased from ₹ 7,011 crores in 2019-20 to ₹ 7,572.20 crores in 2020-21. Only by around ₹ 500 crores! The Ministry had reportedly sought ₹ 12,000 crores. In such a scenario, has the Government assessed the lag in funding for the sector as a whole? Is the budgetary allocation of the sector enough or is the Government going bankrupt to be not able to provide the needed funds for the sector?

My seventh point is that there is a policy gap regarding agro-based industries in the MSME sector on behalf of the Central Government. India is an agrarian country. So, India has an ample scope in agro-based industries, and agro-based industries are obviously in MSME sector. We have a lot to produce like potato chips, food and fruit processing, jute, cotton, tea, etc., and can flourish MSME sector by developing such agro-based industries. But, unfortunately, the Central Government has no definite and constructive positive policy for the development of agro-based industries in our country as well as the MSME sector.

I am coming to the end, Madam Vice-Chairperson. Now, let me come to the importance of the MSME sector for the country, which is already flourishing in Bengal. The MSME sector in India is key to the growth of the country' s economy. Around 75 million MSMEs contribute to about a third of the GDP and 45 per cent of the manufacturing output of the country. These companies also provide employment to more than 110 million people in our country. But the sector has been facing issues that need correction and holistic policy intervention. Let us follow, at least, a bit the Bengal model of MSME and let us work together for India. Now, with the outbreak of Coronavirus, the industry is set to make further losses and see job losses as well. Considering the impact of the virus on the economy of the country, consumption and demand will decrease, hampering the economy as a whole.

[Ms. Dola Sen]

Overall, I would urge the Government to pay heed to the demands of the MSME sector and ensure that it is well funded, its operations are streamlined, it has proper access to finance, its payments are made on time, and it functions in an environment of economic progress and not lag.

Bengal is number one in the nation as far as MSMEs are concerned. Why we do not follow Bengal model in this respect? Let us work together to make India the number one MSME country in the world.

At the end, hon. Mr. Prime Minister, you are going to address the nation at 8.00 p.m. tonight on coronavirus. Good. We are looking forward to that. But, please, do come to the Parliament and address the Parliament regarding everything, coronavirus, MSME and development of the country. Do come to our House also, do come to Parliament, do come to Rajya Sabha. Thank you.

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Thank you, Madam Vice-Chairman, for giving me the opportunity to speak on MSME.

**श्री जयराम रमेश:** महोदया, कैबिनेट मंत्री नहीं हैं। मैडम, एमएमएमई के कैबिनेट मंत्री को यहां मौजूद होना चाहिए।

**एक माननीय सदस्य:** वे अभी आ रहे हैं।

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): The MSME sector is a vital and emerging sector in the Indian economy and amounts to a major proportion of the manufacturing sector particularly. With India being a labour-intensive economy with a huge demographic dividend on top, the contribution of MSME sector in employment generation is of primary importance. It also paves the way for innovation, exports and inclusive growth of the economy. This sector is in excess of 28 per cent of the GDP and 45 per cent of manufacturing sector output. Apart from the short interval between 2009 and 2012, the contribution of the MSME sector has been constantly higher than the overall industrial growth rate. For instance, the industrial growth rate was 6.6 per cent in 2015-16 as compared to 7.62 per cent for the MSME. This sector provides employment to an estimation of 12 crore people through around 6.3 crore enterprises. As per the Boston Consulting Group Report, this sector required almost ₹ 37 lakh crore of investments. But only ₹ 17.4 crore is available for this sector by 2019. They

are getting forty per cent loan from the private enterprises, relatives, friends and other private people and only sixty per cent from bank and banking institutions, financial institutions. This is a very big gap. The investment that is required by the sector is not provided by the Government. The RBI constituted a Committee, U.K. Sinha Committee. The Committee also gave thirty-five suggestions. As on today, they are not getting implemented. Last year, that report came. They suggested that ₹ 5,000 'distressed funds' and ₹ 10,000 'fund-to-fund' should be there to support the new venture capital and other organizations. As on today, nothing is there from the Government side. The Ministry requested for ₹ 12,000 crore from the Finance Ministry. But they allotted only ₹ 7,500 crores. That shows what importance this Government is giving to the MSME sector.

Madam, MSME sector plays a very key role. The newly-formed Telangana Government is also taking very good steps to promote this sector. One of the major barriers to the growth of the small business sector in the country relates to the Ease of Doing Business. Earlier, our rank was around 100. Recently, our rank has reached around 70 after removing so many limitations; that is coming down. Telangana has been one of the successful models for this in easy clearances and certification highlighted in the innovation policy of the Government of Telangana. The Government Innovation Policy is centred around five pillars, namely, support for building physical infrastructure; creation of sustainable funding channels; facilitating the right environment for developing human capital; engaging with industry to actively promote innovation; and additional incentives to start-ups in the rural and social enterprise space.

The Government of Telangana seeks to promote start-ups with three types of incentives. One is 'Incentives for Incubators'; second is 'Incentives for Startups'; and the third is 'Non-fiscal Incentives'. In the first incentive, they reimburse the paid stamp duty and registration fee. In the 'incentives of Startups', they will reimburse the State GST up to maximum turnover of ₹ 1 crore per annum for first three years; reimbursement of fixed per cent of marketing cost; financial support for the patent filing; recruitment assistance to support growth; and grants for higher growth rate startups. In the final 'Non-fiscal Incentives', they are supporting self-certifications. There is no need of any inspection. 'Inspector Raj' is closed in Telangana.

[Dr. Banda Prakash]

Madam, I want to bring to the kind notice of the hon. Minister that MSME is a very, very important area for the Indian economic growth. This sector is facing challenges and does not get the required support from the concerned Government Departments and banks. ...*(Time-bellrings)*... Madam, there are so many limitations such as absence of adequate and timely banking finance, limited capital and knowledge, non-availability of suitable technology, low production capacity, ineffective marketing strategies, constraints of modernization and expansion and non-availability of skilled labour at affordable cost. The amount under Mudra allowance that they are giving now is just ₹ 10 lakhs, without any security. Even the Committee had recommended for it to be increased up to ₹ 20 lakhs. The need of the hour for us is to learn from each other, drawing upon the experiences, and identify best practices and policies. These in turn have to meet local conditions and circumstances. There is no second opinion that SME policies need to be strengthened for achieving the socioeconomic goal of employment growth and social justice along with individual aspirations.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Madam Vice-Chairperson, MSME sector in India is key to the growth of Indian economy. There are about 75 million MSMEs which contribute to one-third of the GDP of the country and 45 per cent of the manufacturing output of the country. These MSME companies provide employment to more than 110 million Indians. Therefore, the sustained growth of MSME and good health of MSME are very important factors in achieving India's GDP growth targets.

Madam, I would like to bring to the attention of the hon. Minister two main concerns which I have, and I hope the hon. Minister would address them. The first concern is GST payments. Madam, MSMEs find it difficult to make GST payments within 20 days of raising an invoice when they get payments from the buyers for almost 90 days. GST payment obligations have made it a perennial working capital problem for the MSME sector throughout the country. Therefore, it is imperative on the part of the Government to address this problem instantaneously. My suggestion in this regard would be there should be a long window for the payment of GST and for the filing of returns for MSME filers. There should also be a reduction in the penal interest rate on late payments for MSME in order to encourage the MSME sector under a certain threshold of revenue.

The next point that I would like to bring to the notice of the hon. Minister is financial problems. This is the second concern that I would like to bring forth to the hon. Minister. Credit plays a vital role in the development of MSME as cheap funds can increase their competitiveness. So, increasing the competitiveness is very important for the MSME sector because it contributes almost one-third of the GDP and provides maximum employment. Due to their small scale, MSMEs are not able to raise the risk capital or give substantial collaterals to get bank loans. Therefore, the Government should ensure timely credit to the MSMEs to the extent that they are not starved of the finances. Andhra Pradesh is leading by example here, which is promoting lending to the MSMEs, on the basis of their size, from ₹ 25 lakh in the form of bank loans and up to one crore rupees for a medium scale industry. This has led to the establishment of 6,572 MSME units in Andhra Pradesh in the last nine months or so.

In conclusion, I acknowledge Gadkariji's role in empowering women by helping them become entrepreneurs. He has recently mentioned that there are now 80 lakh women entrepreneurs in MSME sector in the country, a commendable jump of 38 per cent. Therefore, there should be some reserved products mandatorily to be produced by MSMEs and they should be assured of purchases by the Government. A major share shall come from MSMEs, if India wants to achieve 5 trillion dollar economy as desired by the hon. Prime Minister. So, I request the hon. Minister to address both the concerns, namely, the finance problem and the GST problem which are being faced by the MSMEs.

**श्री राजाराम** (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कार्यकरण की चर्चा पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बोलने के खड़ा हुआ हूं। व्यापार के वर्तमान परिदृश्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को देश के विकास के इंजन के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये विकास के साथ-साथ लोगों को रोज़गार के समान अवसर भी प्रदान करते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने का काम करते हैं। महोदया, देश में 60 मिलियन से अधिक छोटे और मध्यम व्यवसाय हैं जो 100 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करने का काम करते हैं। भारत में होने वाले कुल निर्यात में लघु एवं मध्यम व्यवसायों का लगभग 45 फीसदी हिस्सा है, लेकिन इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद भी छोटे व्यवसायी अभी तक डिजिटल तकनीक से वंचित हैं। मैं सरकार से चाहूंगा कि वह इस बात का संज्ञान ले और व्यापारियों को नयी तकनीक उपलब्ध कराए, जिससे देश में किसी भी स्थान पर बैठकर वे मोबाइल से अपने व्यापार को संचालित कर सकें।

[श्री राजाराम]

**3.00 P.M.**

महोदया, MSME क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद 29 फीसदी है और यह 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। देश में manufacturing, जैसे कपड़ा, चमड़ा, हीरा, आभूषण और वाहन आदि चार-पांच क्षेत्र हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रोज़गार पैदा होता है और इनसे तमाम उद्यमी जुड़े हुए होते हैं, लेकिन पूंजी की कमी और खपत घटने से इन क्षेत्रों में गहरी मंदी चुनौती का विषय बना हुआ है। हुनर और उत्पादों का बाज़ार नहीं मिल रहा है और सस्ते आयात और बदलते फैशन के सामने पारम्परिक उद्योग अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। ऐसे में माकूल माहौल और सरकारी मदद की जरूरत है। MSME उद्योग को कर्ज़ देना सरकारी बैंकों की प्राथमिकता में नहीं होता है, जो इस बात से पता चलता है कि अब बैंक इन्हें 69 परसेंट से घटाकर 46 परसेंट कर्ज़ दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि बैंकों की इनके प्रति किस प्रकार की उदासीनता है। महोदया, मैं आज़मगढ़ से आता हूं। वहां पर मऊ में बनारसी साड़ी मिलती है, जो देश में ही नहीं, विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहां छोटे-छोटे उद्योग हैं, जिनमें पांच, दस, पंद्रह या बीस लोगों को रोज़गार मिलता था, लेकिन आज वहां पर स्थिति यह है कि बैंक उन्हें कर्ज़ नहीं देता है। ऐसी स्थिति में वे साहूकारों से या प्राइवेट बैंकों से कर्ज़ ले लेते हैं। कर्ज़ की दर ऊंची होने के नाते और दूसरी तरफ सही बाज़ार नहीं मिलने की वजह से वे कर्ज़ के बोझ तले दबते चले जाते हैं। उन पर कर्ज़ का बोझ इतना अधिक हो जाता है कि वे घाटे में चले जाते हैं। परिणाम यह है कि जो उद्योग कभी रोज़गार देने का काम करते थे, आज उनका रोजगार बंद हो गया है, उनके कारखाने बंद हो गए हैं और वे लोग दिल्ली, मुम्बई या कहीं और जाकर नौकरी खोज रहे हैं - यह स्थिति आज हो गयी है। महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि हमारी तरफ, चाहे भदोही का कालीन उद्योग हो, चाहे मऊ, मुबारकपुर की बनारसी साड़ी हो, चाहे फिरोज़ाबाद का कांच का सामान हो या अलीगढ़ का ताला-चाबी का उद्योग हो - जहां एक ओर आप स्वरोज़गार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जहां आप लोगों को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, वहीं ये सारे रोज़गार आज आईसीयू में चले गए हैं। ये उद्योग किसी तरह से ज़िंदा हैं, बस इतना ही है - 80 परसेंट तो बंद हो गए हैं। इस पर सबसे ज्यादा मार तब, जब आपने नोटबंदी कर दी। उनका जो काम होता है, वह कैश का होता है - दस-पंद्रह लोग काम करते हैं और कैश में काम होता है। महोदया, मैं आज आपसे उम्मीद करूंगा कि मुझे थोड़ा सा संरक्षण मिलेगा - मेरा टाइम एक-आध मिनट बढ़ जाएगा, इतनी मैं आपसे request करूंगा - मैं कभी-कभी ही बोलता हूं।

वे आज आईसीयू में चले गए हैं। उनको सबसे बड़ा धक्का लगा, जब आपने नोटबंदी कर दी। नोटबंदी में उनके पास पैसे नहीं थे। जब उनके पास पैसे नहीं थे, तो वे अपना

रोजगार कैसे चलाएं? 80 परसेंट रोजगार तो बंद हो गए थे, चाहे हमारी बनारसी साड़ी की बात करें या भदोही के कालीन की बात करें या अलीगढ़ के ताले की बात करें या आपके फिरोजाबाद के कांच के सामान की बात करें। मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने प्रदेश की बात कर रहा हूं। करीब-करीब 80 परसेंट तो उनकी कमर टूट गई और अभी इससे भी नहीं उबरे थे, तब तक आपने उस पर जीएसटी लाद दिया। जीएसटी लगाते ही, जितने रोजगार करने वाले लोग थे, वे रोजगार बंद करके अपनी नौकरी खोजने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय महोदया आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इन उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सरकारी बैंकों से बात करें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में कम ब्याज पर कर्ज़ या ऋण मिले और उनके लिए उपयुक्त बाजार मिले, क्योंकि अगर वे सामान भी बना लेते हैं, तो बाजार तक उनकी पकड़ नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है, जिससे वे अपना माल भी नहीं बेच पाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि उनके लिए बाजार उपलब्ध कराया जाए और उनके लिए कर्ज़ की व्यवस्था की जाए।

मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस एक-दो सुझाव या जानकारी या सवाल माननीय मंत्री के समक्ष रखकर अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि देश में एमएसएमई इकाइयों या इससे जुड़े उद्यमियों में और कार्यबल में कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित है और उन्हें कितना कर्ज़ निर्गत किया गया है, जिससे वे लोग स्वावलंबी बन सकें? क्या इस वर्ग विशेष के कौशल विकास की कोई योजना चला रही है? यदि हां, तो अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षण देकर उद्यम स्थापित कराए गए हैं? यह मेरा पहला सवाल है और दूसरा सवाल करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ग्रामीण क्षेत्र में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के विकास में पूंजी एक बड़ी अड़चन है। क्या सरकार इस दिशा में विशेष प्रयास कर रही है, जिससे उत्पादित सामान की बिक्री सुनिश्चित हो सके?

**श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला** (गुजरात): माननीय महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इन्टरप्राइज़, एमएसएमई पर हो रही चर्चा पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहले के ज़माने में जब छोटे-छोटे लघु उद्योग होते थे, तो परंपरागत, मतलब जो पुराने लोग थे, उनको पुरखों की जायदाद की तरह, जो मिलते थे, उसी तरह का वे छोटा-मोटा कारोबार करते थे। दूसरे जो लोग थे, उनकी जो प्रणाली और जो संस्कृति थी, उसके हिसाब से वे कारोबार करते थे। एक तीसरा वर्ग है, जो नए इनोवेशन हैं, आज जिस तरह भारत बदल रहा है, नए-नए आइडियाज़ हैं, उनके हिसाब से आज नई पीढ़ी काम कर रही है। मैं खास तौर पर यह कहना चाहूंगा कि आज गांव के क्षेत्र से लेकर छोटे शहर और बड़े शहर तक एमएसएमई के जो छोटे-छोटे कारोबार चलते हैं, छोटे-छोटे बिज़नेस चलते हैं, इसके लिए सरकार ने जो किया है, मैं उसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पहले एमएसएमई के अंदर जो

[श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला]

अपना बिज़नेस करना चाहते थे, अगर उनको एक करोड़ से ऊपर जाना पड़ता था, तो उनको लोन नहीं मिलता था। आज की तारीख में उन्होंने इसे करोड़ से बढ़ाकर दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे पांच करोड़ रुपये कर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एमएसएमई पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी है। हमारा जो अर्थतंत्र है, उसमें 29 परसेंट की जो जीडीपी ग्रोथ है, उसके अंदर जो लोग काम करते हैं, जो उनकी इंडस्ट्री चलाते हैं, वे हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी हैं। वैसे देश के अंदर, कई अलग-अलग जगहों पर कहीं कॉटन का उद्योग है। अभी हमारे साथी बता रहे थे, वे कांच के उद्योग की बात कर रहे थे, मिट्टी के बर्तन की बात कर रहे थे, ये सब हमारी धरोहर हैं। इसको जब हम मार्केट में बेचते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम यह होती है कि उनको इन्हें बेचने का पूरा ज्ञान नहीं होता है। उनको यह पता नहीं होता है कि अपने प्रोडक्ट्स की सेल कैसे करें, कैसे प्रोडक्ट्स को मार्केट में पेश करें, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन होता है, वह बहुत सारे लोगों का एक जैसा होता है। वे लोग कम पढ़े-लिखे होते हैं। वे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन उनको इसका आइडिया ही नहीं रहता है कि मार्केट में उसको कैसे बेचें? उनको पता ही नहीं होता है कि टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करना चाहिए, वे लोग टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से उपयोग कर नहीं पा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, उनके लिए अलग से एक वेबसाइट होनी चाहिए। वे लोग जो भी प्रोडेक्ट बनाते हों, उनकी एक अलग वेबसाइट होनी चाहिए। उनको अपने प्रोडेक्ट्स को बेचने के लिए हर जगह पर स्थान मिलना चाहिए। हमारे देश में जो लघु उद्योग चलाने वाले लोग हैं, उनकी संख्या 11 करोड़ से ज्यादा है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहूंगा कि गांव के अंदर 51 परसेंट से ज्यादा लोग स्माल स्केल की इंडस्ट्री चलाते हैं और 45 परसेंट से ज्यादा लोग उनके अंदर काम करते हैं। इसी तरह से अरबन एरिया के अंदर 49 परसेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर भी 55 से 56 परसेंट लोग काम करते हैं। इसी तरह से ट्रेडिंग के अंदर करीब 36 परसेंट एमएसएमई के अदंर लोग काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 31 परसेंट लोग काम करते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर 33 परसेंट लोग प्रोडक्ट करते हैं और काम भी करते हैं। इसी तरह से अलग-अलग जो हमारी यूनिट्स हैं, उनके अंदर जो लोग काम करते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं होती है, लेकिन उससे भारत की एक पहचान बनी रहती है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर कई लोगों ने एमएसएमई के बारे में बोला है। अभी हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि आप लोग गरीबी हटाने की बात करते हो और गरीबी हटा नहीं रहे हो। इसके अलावा वे बहुत सारी बातें कह रहे थे। आज वे सदन में नहीं हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमने उनको नहीं हटाया है, जनता ने

उनको हटाया है। दूसरी बात यह है कि यहां पर कई माननीय सदस्य भी बोल रहे थे, अगर वे यहां पर बैठे होते, तो मैं उनको बताता, मैं उनको याद दिलाता। अभी एक बंगाल के सदस्य बोल रहे थे। ...**(व्यवधान)**...

**श्रीमती जया बच्चन** (उत्तर प्रदेश): बंगाल की सदस्या बोल रही थीं।

**श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला** : हां, बोल रही थीं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि सिंगूर में नैनो टाटा का प्रोजेक्ट था, स्माल स्केल इंडस्ट्री वहां पर थी, तो वह वहां से गुजरात क्यों चली गई? अगर आप उनको प्रमोट करते, तो वह इंडस्ट्री गुजरात कभी नहीं जाती। इसके बार में आपको सोचना चाहिए था...**(व्यवधान)**...

**श्रीमती जया बच्चन:** उसमें फारमर्स को बचाना था। आप आधी चीज़ मत बोलिए।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन):** कृपया बीच में न बोलें।

**श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला:** उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। महोदया, श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें वे पूरे भारत को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। हमारा तो नारा ही है कि "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।" इसके साथ ही, मैं ज्यादा न कहते हुए, अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूं, जय हिन्द, वंदे मातरम और आभार।

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Madam, let me, first of all, join all my colleagues in acknowledging the dynamism of the Minister of MSME. Mr. Gadkari is a very experienced administrator. He practices a very non-toxic brand of politics which makes politics acceptable. He gives everybody a sense of participation and a feeling of consultation. His appointment as the Minister of MSME has brought a fresh air of dynamism into a Ministry that is normally not known for dynamism.

Let me begin first by saying that Mr. Gadkari is known to speak his mind. He is known to say what is on his mind. Today, I would like him to take the House into confidence and really tell us this. What is the impact of demonetization and the GST on the MSME sector? I believe the GST was a major reform. It was badly needed. I congratulate the Government on bringing in the GST. However, the manner in which the GST was implemented, the hurry with which it was implemented has adversely affected the MSME sector particularly. I have no problem if you want to formalize an informal economy. That is a worthwhile objective. However, the fact is that the double shock of demonetization in November 2016 and the GST in July 2017 has created

[Shri Jairam Ramesh]

major, major dislocation in the MSME sector. You can go to any cluster to see this. You can go to Tirupur. You can go to Avadi. You can go to Jalandhar. You can go to Ludhiana. You can go to Pune. You can go to Aligarh. You can go to Howrah. You take any of the clusters in India and you will see impact of the GST and demonetisation. Now demonetisation is a reality. The GST is a reality. Let us look ahead. What are you doing to enable the MSME sector overcome the shocks of demonetisation and the GST? Please do not tell us that they were not shocks. They were shocks. One was a welcome shock. One was an unwelcome shock. But what are we doing to strengthen the MSMEs to deal with the fallout and implications of demonetisation and the GST? This is my first question to the hon. Minister.

My second point to the hon. Minister is this. I think it is time we changed the definition of MSMEs. For many years, I have been arguing that India is the only country in the world which defines the MSME on the basis of investment and plant and machinery. I have been arguing that we should define the MSME in terms of employment, because employment is the biggest challenge that India faces. However, after the GST, I have changed my mind. I believe that there is merit in defining the GST on the basis of turnover, not necessarily employment. For this, the MSME Act of 2006 needs to be amended. I would like the hon. Minister for MSME to enlighten us whether there is any plan for changing the definition of MSMEs. If you define the MSME in terms of turnover, compatibility with the GST and the GSTN becomes easier, because the entire GSTN information backbone is based on turnover. It is not based on capital employed. We passed the MSME Act in 2006 which defines the MSME in terms of capital employed. I would request the hon. Minister for the MSME to educate us on this aspect.

The third point I would like some enlightenment on is this. We have passed the Insolvency and Bankruptcy Code. But the Insolvency and Bankruptcy Code has little meaning for MSME sector. It is of relevance for the large organized sector of industry but for the MSME sector, as I have argued repeatedly on earlier occasions, we need a completely new mechanism for insolvency and bankruptcy, which is a major issue as far as MSME is concerned. This too, I think, will require amendments not to the IBC but amendments to the MSME Act of 2006 and I would like the hon. Minister to make a few comments on this.

Then, Madam, delayed payments is the single biggest problem for the MSME sector. In 1993, Parliament passed the Delayed Payments Act. Under the Delayed Payments Act, 90 days is the maximum period given for liquidating all payments for the MSME sector. But, we know and anybody, who has dealt with MSME sector, knows that payments are not made on time and the biggest culprits are public sector companies and Government Departments. I would like the hon. Minister to tell us what he is doing to enforce the Delayed Payments Act in letter and spirit so that one cause of sickness in the small and medium sector is obliterated and eliminated. Then, I ask him a question on cluster development. India has over 150 industrial clusters. In fact, you have clusters in every State. They are specialized clusters and some of them are generalized clusters but the characteristic of an MSME is a cluster. And your State of Maharashtra is the best example of a cluster. Thana-Belapur is a cluster; Pimpri-Chhinchwad is a cluster; Aurangabad is a cluster. Nagpur is now emerging as a cluster. What are we doing for cluster development? Cluster development requires infrastructure, cluster development requires technology and cluster development requires finance. The whole future of the MSME sector depends on cluster development and instead of having smart cities, in my view, we should have smart clusters. The first target for smart cities should be MSME clusters and I would like the hon. MSME Minister to take this idea forward.

Finally, Madam, KVIC and traditional industry is very much part of the mandate of the MSME Ministry. KVIC is a statutory body, established by an Act of Parliament. I think the time has come to corporatize KVIC. We need to professionalise KVIC. We need to bring modern management, modern finance and modern marketing into KVIC. The old 1956 model of KVIC, in my view, has outlived its utility and we need to think bold and this Minister is known to think boldly, if not always realistically. I think in this matter he would be doing the nation a great service if he were to give a new future and direction to KVIC and traditional industry. We had in 2005 started a scheme called SFURTI, Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industry. Mr. Alphons is here. One of the objectives of the scheme was to revive the coir industry in Kerala. There were many industries —handloom industry, handicraft industry and coir industry —and this SFURTI scheme was launched in a major way to revive traditional industry because it is important from the point of view of exports and it is important from the point of view of employment as well. I would like the hon. Minister to enlighten us and educate us as to what he is doing in this area.

[Shri Jairam Ramesh]

Finally, Madam, many Members have spoken about the U.K. Sinha Committee report that was submitted to the RBI in 2019. Could you tell us what you are doing by way of implementation of the recommendations of the U.K. Sinha Committee? Have you accepted those recommendations? In my view, it is one of the most comprehensive reports for the revival and further growth of the MSME sector and I think the country will benefit if the recommendations of the U.K. Sinha Committee, which go all the way across the board, are implemented seriously by the Government. With these few words, I would once again say that the MSME sector is fundamental to economic growth in India. It requires a constant push. I believe, the Minister is in a position to give this push but to give the push it has to recover from the two shocks that were given to it in 2016 and 2017. Unless that recovery takes place, I am afraid, we are not going to move very far in the MSME sector. Thank you, Madam.

**श्री राम विचार नेताम** (छत्तीसगढ़): उपसभाध्यक्ष महोदया, मुझे इस महत्वपूर्ण विभाग के बारे में बोलने का जो अवसर दिया गया है, उसके लिए मैं आपको, अपने दल को और हमारी पार्टी के जो सचेतक हैं, जिन्होंने मेरा नाम आप तक प्रस्तुत किया, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदया, आज जब पूरी देश-दुनिया नव-उदारवाद के युग में चल रही है, जब MSME पूरी दुनिया में फैल रही है और छोटे-छोटे उद्योग खतरे में हैं, तब मोदी सरकार ने इस औद्योगिक नीति और कार्यक्रम के केन्द्र में MSME को लाकर जो एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है और सिर्फ निर्णय ही नहीं लिया, बल्कि ऐसे हाथों में इस काम को सौंपा है, मैं आदरणीय मंत्री, माननीय नितिन गडकरी जी का नाम बहुत ही आदर के साथ लेना चाहूंगा, जिन्होंने मंत्रालय का काम सिर्फ कागजी आधार पर नहीं किया, बल्कि मुझे पूरी तरह से अनुभव है कि वे जिस विभाग को संभालते हैं, जहां काम करते हैं, वे उसकी गहराई तक जाकर लोगों तक उसका लाभ कैसे पहुंचे और उसमें क्या-क्या अन्वेषण किया जा सकता है, कैसे skill को और बढ़ा कर हम उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, यह भी देखते हैं। जब ऐसी शख्सियत, आदरणीय नितिन गडकरी जी के पास यह विभाग है, तो मैं समझता हूं कि पूरे देश को, हम सबको गर्व होता है। ऐसे हाथों में आज देश है, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के हाथों में, जिन्होंने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, सबकी चिंता करते हुए यह काम करने का बीड़ा उठाया है। निश्चित ही मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

महोदया, एक तरह से मैं एक ट्राइबल क्षेत्र से आता हूं। ट्राइबल क्षेत्र में जिस प्रकार से 2014 के बाद हमारी सरकार ने 'Make in India' के माध्यम से लोगों का skill बढ़ा कर

लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे उन्हें स्व-रोजगार के साथ जोड़ा जाए, उन क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में जिसकी विशेषता हो सकती है, हो सकता है कि कृषि के क्षेत्र में उन्हें अधिक लगाव है, तो उन्हें कृषि में जोड़ कर कैसे MSME में जोड़ा जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया। इसी प्रकार से बैम्बू के क्षेत्र में काम करने वाला कोई क्षेत्र है, तो नॉर्थ-ईस्ट में बैम्बू में भी बहुत सारे अच्छे काम होते हैं। इसी प्रकार से हमारे बस्तर के आर्ट्स के बारे में बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं। उसमें हम कैसे skill को बढ़ा कर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन माताओं-बहनों को जोड़ कर उनको कैसे empower कर सकें, और कैसे उनकी skill को बढ़ा कर इस देश की प्रगति में उनका सहयोग ले सकें, अगर यह काम किसी ने किया है, तो माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। यह भी तारीफ की बात है।

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज 'Make in India' ने MSME के आधार को सिर्फ बढ़ाया ही नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र से जुड़ कर इसके संपर्क में आने के बाद न जाने लाखों परिवार की जो आर्थिक हालत थी, उससे उबर कर वे आज अच्छी स्थिति में आ गए हैं। इस चीज़ को हम देखते ही नहीं हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सिर्फ आलोचना करने की बात न करें। अभी इस विषय पर माननीय प्रफुल्ल पटेल जी का बहुत सकारात्मक विचार आया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। इसी प्रकार से आदरणीय श्री जयराम रमेश जी का भी काफी अच्छा सुझाव आया, उनका इस क्षेत्र से काफी जुड़ाव भी रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ सदस्य तो मोदी सरकार की सिर्फ आलोचना ही करते हैं। क्या हम इस संसद में इसी वजह से आए हैं? देश की प्रगति के लिए यदि सरकार अच्छा और सकारात्मक काम कर रही है, तो उसकी बड़ाई क्यों नहीं की जानी चाहिए और उसे सम्मान क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? लेकिन मुझे तरस आता है कि इस तरह से अच्छे काम करने के बावजूद कुछ माननीय सदस्य सरकार की बड़ाई नहीं कर रहे, बल्कि आलोचना कर रहे हैं। हम Make in India के माध्यम से न जाने कितने करोड़ लोगों को जोड़ कर फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि प्रतिवर्ष 75 लाख लोगों को स्वरोज़गार से जोड़ेंगे और अगले पांच सालों में पांच करोड़ लोगों को स्वरोज़गार से जोड़ेंगे। हम यह कल्पना लेकर चल रहे हैं कि MSMEs के माध्यम से 2025 तक 16 करोड़ लोगों को स्वरोज़गार से जोड़ने में सफल होंगे। जब हम इतना बड़ा concept लेकर चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसके लिए हमें बहुत सारे कदम भी उठाने हैं। मैं यह कह सकता हूं कि देश की आज़ादी के बाद इस क्षेत्र में अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। उन्होंने MSME सैक्टर को बढ़ावा देने का काम किया है। यही नहीं, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने नये entrepreneurs को प्रोत्साहन देने का काम भी किया है और local talent को बढ़ावा भी दिया है। हमने यह कोशिश की है कि जो local talent है, उन्हें तराशा जाए और उनकी skills को और

[श्री राम विचार नेताम]

**3.30** P.M.

बढ़ाया जाए, साथ ही उनके लिए हम marketing की व्यवस्था भी करें। इस क्षेत्र में अगर किसी ने उल्लेखनीय काम किया है, तो माननीय नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय नितिन गडकरी जी ने किया है। हालांकि मैं इस पर बहुत अधिक स्टडी नहीं कर पाया हूं, लेकिन फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने तरह-तरह के portals चालू किए हैं, जिस प्रकार से marketing की व्यवस्था की है, जिस प्रकार से skills को बढ़ाने की व्यवस्था की है, यह व्यवस्था की है कि कैसे उन्हें अधिक से अधिक प्रशिक्षित किया जा सके, महोदया, ये यह सब काम प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी की सोच और संकल्पना के आधार पर किए जा रहे हैं। इन कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पूरा संकल्पना के आधार पर किए जा रहे हैं। इन कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पूरा करने का काम किया जा रहा है।

महोदया, हमारे माननीय मंत्री जी में इन कार्यों को करने की स्वयं ही दिली इच्छा और लगाव रहता है। वैसे आपको मालूम ही होगा कि एक बीमार शुगर फैक्टरी, जो बुरी तरह से डूबी हुई थी, उस शुगर फैक्टरी को माननीय मंत्री जी ने अपने हाथों में लिया और वहां के लाखों किसानों के जीवन में ज्योति लाने में सफल हुए, प्रकाश लाने में सफल हुए। जो किसान कर्ज़ में डूबे हुए थे, उन्हीं किसानों की हालत आज ऐसी है कि पूरे प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में उस शुगर फैक्टरी और उससे जुड़े लोगों को मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ-साथ इन्होंने बहुत सारी अन्य चीज़ों को भी जोड़ा है।

महोदया, यही नहीं, कृषि के क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए, वानिकी के क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए, फलोद्यान के क्षेत्र में कैसे मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, MSMEs के माध्यम से बहुत ऊंची कल्पना करके इन्होंने उसे जो विराट स्वरूप दिया है, वह तारीफ के काबिल है। इसी प्रकार से road transport के संबंध में इन्होंने यह कल्पना की है कि कैसे हम हाईवे के माध्यम से मुम्बई को दिल्ली से जोड़ सकें।

इन्होंने जिस प्रकार से, जिस कल्पना के आधार पर किसानों के सेक्टर को हम कैसे जोड़ सकें, किसानों की उपज के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था कैसे कर सकें, इसके लिए इनके पास जो कॉन्सेप्ट था, उसको मूर्त रूप देने का यदि किसी ने कोई काम किया है तो हमारे माननीय मंत्री, श्री गडकरी जी ने किया है, इसकी तारीफ क्यों नहीं की जानी चाहिए। हमें यह बात स्वीकारनी चाहिए।

महोदया, मैं छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल सरगुजा, बलरामपुर जिले की बात कर रहा हूं। बलरामपुर जिले में मुद्रा बैंक योजना का लाभ लेकर जो हमारे आदिवासी किसान हैंड

टू माउथ हुआ करते थे, आज उन क्षेत्रों में भी स्वयं-सहायता समूह बनाकर बहुत सारी बहनें रोजगार अर्जित कर रही हैं और उनके पास 50-50 लाख रुपये की एफडी हो रही है। आप यह क्यों नहीं बोलते? यही नहीं, मैं किसान की बात कर रहा था, हमारे किसान आदिवासी परिवार और हमारे कुसमी परिवार जो साल में 25 लाख रुपये की मिर्ची बेचते हैं, आप बताइये कि इन आदिवासी परिवारों को किससे लाभ मिला? यह इसी सरकार की देन है। उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है, इस प्रकार के जो परिवर्तनकारी निर्णय हुए हैं, उनका लाभ लेकर लोगों का जो जीवन-स्तर था, उसमें आमूलचूल परिवर्तन आया है। यह सोचने की बात है, हम इस बात को समझ सकते हैं।

इसी प्रकार से हमारे बस्तर जिले में जो बस्तर आर्ट है, बस्तर आर्ट के लिए हम क्यों नहीं सोच सकते? हमारी कल्पना है, हम उसे अच्छी मार्केटिंग दे रहे हैं। उनकी स्किल को और कैसे बढ़ाया जा सके, यह काम भी हम कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दुनिया में एकमात्र हमारा भारत देश ही है, जहां हमारे ग्रामोद्योग की कल्पना के आधार पर हम ग्रामोद्योग चलाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामोद्योग का एक विश्वविद्यालय क्यों न स्थापित कर दिया जाए? अगर हम इस विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं तो देश के विभिन्न राज्यों में, उन क्षेत्रों में भी हम इस सेक्टर की अलग-अलग ब्रान्चेज़ बनाकर, कॉलेजेज़ बनाकर उन्हें डिग्री दें, उनका स्किल बढ़ायें, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करें, उनके लिए हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं।

महोदया, केन्द्र की भारत सरकार हमारे प्रदेश की सरकारों को सपोर्ट करती है। सपोर्ट करने के लिए उनके पास क्या है, उनके स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम उनको कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, यह सपोर्ट भारत सरकार करती है। लेकिन बहुत कुछ नीति और नीयत वहां की सरकारों पर भी निर्भर करती है। एक ज़माना था कि पश्चिमी बंगाल कुटीर उद्योग का हब हुआ करता था। क्या कारण है कि आज वहां के सारे कुटीर उद्योग बंद पड़े हैं? क्या कारण है, अलीगढ़ के ताले आज नहीं बिक रहे हैं? क्या कारण है कि आज बनारस की साड़ियां नहीं बिक रही हैं? क्या कारण है कि मिर्जापुर, भदोही का कालीन उद्योग पूरी दुनिया में जाना जाता था, दुनिया में उसकी प्रसिद्धि थी, वे आज क्यों नहीं चल रहे हैं? इन सभी कारणों को देखते हुए हमें इसके निदान की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है।

हमें गर्व है कि आज हम माननीय मोदी जी के कॉन्सेप्ट के आधार पर, न्यू इंडिया के कॉन्सेप्ट के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास हमें उन लोगों का अर्जित नहीं हो रहा है, जो आज दुखी हैं, जो लोग आज बेरोजगार हैं। वे लोग बेरोजगार क्यों हैं, वे यह समझें। लेकिन आज पूरा भारत अपने

[श्री राम विचार नेताम]

आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आज माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश चल रहा है और चल ही नहीं रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। आज यह हमारी स्थिति है। महोदया, यही नहीं, मैं आज आपसे यह कहना चाहूंगा कि ...**(व्यवधान)**...

मोहतरमा, आज वास्तव में यह जो समय आया है, युग आया है, इसने सामाजिक, आर्थिक आन्दोलन में तब्दील कर दिया है। एक तरह से पूरे देश में यह जो मोदी इकोनॉमी चल रही है, इसको हमें समझने की जरूरत है। जिनको नहीं समझना है, महोदया, वे तो कभी समझ नहीं पायेंगे, वे तो सिर्फ गाली ही देंगे, उनका और कुछ नहीं बचा है। मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि वे जितनी ही गाली देंगे और वे माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को जितना ही कोसेंगे, उतना ही नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और 100 गुना अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी। मैं अगले पांच साल की बात कर रहा हूं। अगले पांच सालों में जो स्थिति है, उसमें जो आमूल-चूल परिवर्तन आयेगा, उसमें विपक्ष जो सामने बैठा हुआ है, शायद वह दिखायी न दे। यह भी स्थिति है। यह भी स्थिति है, क्योंकि देश का मिजाज़ बदल चुका है, देश तेजी से आगे बढ़ चुका है। देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसको अगर आप अगर नहीं पहचानेंगे, उसको आप परखने में देरी करेंगे, तो मध्य प्रदेश में जो हाल हुआ, कर्नाटक में जो हाल हुआ, बाकी राज्यों में भी यही स्थिति होने वाली है। किसी गलतफहमी में मत पड़िए। एक ज़माना था कि एक नेहरू का युग था, गांधी जी का युग था, लेकिन यह युग, यह मोदी जी का युग है और यह युग कम से कम 50 साल रहेगा, 50 साल! इसको मान कर चलिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी भी समय है। ...**(व्यवधान)**... अभी भी समय है, समझिए। ...**(व्यवधान)**... सुधर जाइए और आप मोदी जी का गुणगान करने लगिए और सरकार का जो सही कदम है, जो काम सही हो रहा है, उसकी तारीफ करिए। ...**(समय की घंटी)**... इसलिए मोहतरमा, मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं, आपसे विनती करता हूं कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, जिस प्रकार से MSME में काम हो रहा है, उसमें हम और आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप सब सहयोग करिए, सहयोग करते रहिए। अगर सहयोग नहीं करेंगे, तो एक-एक राज्य जो आपका जा रहा है, धीरे-धीरे आप कहां होंगे? "इक दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा।"

महोदया, मैं यही कहना चाहता हूं और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्रीमती जया बच्चन**: उनसे कहिए कि एक कहावत है कि "Pride comes before a fall". ...*(Interruptions)*... वे घमंड थोड़ा कम करें। ...**(व्यवधान)**... जब पेड़ बहुत भारी हो जाता है, तो झुक जाता है। So, just remember that.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Madam Vice-Chairman, I thank you for giving me this opportunity and I am so happy that our Madam is in the Chair. I want her to come back again. We always appreciate women leadership. Now, I also appreciate our vibrant Minister of Road Transport and Highways, Nitin Jairam Gadkari*ji* for progressing in a right direction. He has called for a green, pollution free travel. The distance travelled should be very safe with safety and comfort. He has had a vision for smart infrastructure and transportation in India. He has launched an initial plantation drive of about 1,500 kilometers of national highways at a cost of ₹ 3,000 crores. It is greenery plantation drive. Now, he managed to increase the highway construction from 14 kilometer per day to 27 kilometer per day, which is a great achievement. He has now started installing electric vehicle chargers in all Government buildings. He has ensured that the public transportation like buses and metros should run on ethanol and electricity. This is a standing example of his great leadership. Also, he has mandated that one per cent of the total cost of the NH contract will go to green corpus fund for plantation purposes. Now, I come to the most important sector, the MSME sector. It is poised for a mega transformation in the year 2020 with the launch of trendy yet affordable e-market places like Alibaba. Sir, Khadi products, about which Jairam*ji* also mentioned, to appeal to the masses and digital data-based credit ratings to help entrepreneurs avail loans. So, the MSME sector contributes 21 per cent to the GDP and 48 per cent to the exports about which all of us have mentioned. There is an urgent need for major reforms. Policy interventions towards ensuring timely availability of low-cost credit, improving Ease of Doing Business and technology upgradation to take on the formidable challenge of creating millions of jobs and achieving a large scale import substitution. Sir, millions of jobs can be created through this sector. The Centre ambitions a contribution of about 2 trillion from Micro Small and Medium Enterprises as India eyes to become a 5 trillion dollar economy by 2024. The Union Minister has also got a target of creating 5 crore additional jobs. India has more than 50 million small and medium enterprises which face the problem of liquidity crunch. All of us have explained about it. Out of this, only 15 per cent gets access to formal credit due to the trust deficit and they lack collateral security. They find it a risky investment and for the ones who get access to formal credit, they have to wait for four to six weeks to get the loans processed, that too at a staggering rate of 14 to 16 per cent. So, I need restructuring of these loans to help the sick units, restructuring of their collateral security to pump in more financial credit to

[Shrimati Vijila Sathyananth]

support the sick units. Nowadays, the scenario creates a deep financing gap of 1 trillion in the market and hence the small and medium entrepreneurs are under-banked and under-served. ...*(Time bell rings)*... I need to make one very important point. We sought a fund of ₹ 10,000 crores to buy equity up to 10 per cent for small business, but, the textile industry is the most affected. We appeal to the hon. Prime Minister and to the Minister for Micro, Small and Medium Enterprises to give one year moratorium for repayment of principal and interest amount to the textile and clothing industry. I wanted to mention this in front of the hon. Minister of Finance as well, but, through our Minister of Micro, Small and Medium Enterprises, I want to take it to the Minister of Finance to give one year moratorium period for repayment of principal and interest amount to textile and clothing industries in Tiruppur, Coimbatore, Erode, Namakkal and all other parts of Tamil Nadu. Sir, the textile mills are suffering. They are in a panic situation due to the Coronavirus. All the employees are migrant employees. They have come from different States. They come from far off places using public transport. Sir, constant preventive measures are being taken, but, the migrant workers want to return to their native homes, because the situation is getting intensified ...*(Time bell rings)*... resulting in mass stoppage of production in the industry. There is steep reduction in demand due to sudden stoppage of exports, imports and also domestic sale due to the closure of malls and retail showrooms. Sir, all the major showrooms and malls are being closed. The industry is likely to face unprecedented and severe loss. They need immediate financial relief to mitigate the crisis. Madam, I am seeking financial measures, including one year moratorium for these MSME groups, to help these MSMEs. Thank you for giving me this opportunity.

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन)**: सदस्यगणों द्वारा की चर्चा पूरी हुई। अब माननीय मंत्री जी अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे।

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री; तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी)**: सम्माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं सभी सम्माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं यह केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन्होंने इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए और उनका यह मार्गदर्शन भविष्य की नीति बनाने के लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं हृदय से सभी सम्माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।

सम्माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, जो हमारे social, economic thoughts हैं, वे महात्मा गांधी जी को हमारे विचार धन के रूप में स्वीकारते हैं। गांधी जी ने यह कहा था कि we need maximum production, with involvement of maximum number of persons. हमको उत्पादन भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए। स्वाभाविक रूप से, उन्होंने यह कहा था कि जो समाज के शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, जो socially, economically, educationally backward हैं, जो आखिरी पायदान पर खड़े हैं, उन लोगों का पहले विचार होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी अपने सामाजिक, आर्थिक चिंतन में यही बात कही थी। इसी बात को केन्द्र बिन्दु मानकर हमने आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो नीति बनाई है, उसका सार भी इन्हीं विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास", यही इस पूरी पॉलिसी का सबसे बड़ा सेंट्रल प्वाइंट है। महोदया, मैं छोटा-सा उदाहरण बताऊंगा कि जब गरीब आदमी को technology मिलती है, तो उसका फायदा कैसे होता है? जब मैं पांच साल पहले ट्रांसपोर्ट मंत्री बना, तब हमारे यहां आदमी, आदमी को खींचने का काम करने वाला साइकिल रिक्शा था। एक करोड़ लोग आदमी, आदमी को खींचने का काम करते थे, जो कि अमानवीय था। जब मैंने बिल रखा था, उस समय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोक सभा में कहा था कि डा. राममनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं इस रिक्शा में कभी नहीं बैठूंगा।

**[उपसभाध्यक्ष, प्रो. एम.वी. राजीव गौडा** *पीठासीन हुए]*

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जिस दिन यह प्रथा बंद हो जाएगी, वह इस देश का सुनहरा दिन होगा और हमने निर्णय किया, एक्ट लाए और mechanized driven E-rickshaw लाए। आदरणीय महोदय, एक करोड़ आदमी, आदमी को खींचने का काम कर रहे थे। इसमें क्लासिफिकेशन करना उचित नहीं होगा, पर उनमें से 70 परसेंट लोग Scheduled Castes, Scheduled Tribes और minority community के थे। आज आप नॉर्थ-ईस्ट में जाइए, सब जगह पर जाइए, यह आदमी, आदमी को खींचने वाला रिक्शा, mechanized driven E-rickshaw से रिप्लेस हुआ है। एक करोड़ लोग थे, जिनको technology ने जीवन दिया। अब हमारा प्रयास है और आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैंने आग्रह से यह कहा है कि अरबन एरियाज़ में हमारे उद्यमियों और उद्योग को विकसित करने के लिए और रूरल एग्रीकल्चर में डेवलप करने के लिए अलग से विचार करना होगा। हमारी 30 परसेंट पॉपुलेशन ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में, ट्राइबल में है, जो रोजगार के लिए शहरों में आई हुई है, इसलिए हमारा पहला emphasis है कि इसी विचार के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, ट्राइबल्स क्षेत्र में और जो 115 Aspirational Districts हैं, उनके लिए कैसे काम करें? इसके लिए हमने चार-छः क्षेत्रों पर कुल्हड़ में चाय देना mandatory करने का निर्णय किया। इसी आधार पर यह निर्णय किया कि चार हजार करोड़ की अगरबत्ती की लकड़ी की कंडियां import हो रही थीं —मैं कभी-कभी एक बहुत विनोदी example देता हूं। आप लोग आइसक्रीम

[श्री नितिन जयराम गडकरी]

खाते हैं, जो आइसक्रीम खाने का चमचा था, वह भी चाइना से import हो रहा था, तब मैंने मजाक में कहा था कि क्या हमारे देश में चमचों की भी कमी है? वह भी बाहर से आ रहा है। हमने उनके ऊपर अब 30 परसेंट ड्यूटी लगाई है और ड्यूटी लगने के कारण अगरबत्ती कंडियां इन सब चीज़ों को खादी और ग्रामोद्योग के अंतर्गत प्रोत्साहन मिला। जयराम रमेश जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे लिए खादी ग्रामोद्योग विलेज इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात यह है कि हमारे देश में एमएसएमई बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ में 29 परसेंट एमएसएमई का contribution है। हमारी manufacturing में 33 परसेंट एमएसएमई का contribution है। हमारा 48 परसेंट एक्सपोर्ट एमएसएमई में होता है। एमएसएमई ने अभी तक करीब 11 करोड़ से 12 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि यह करते समय ग्रामीण कृषि का विशेष ख्याल रखा जाए। आपने विशेष रूप से कॉयर का उल्लेख किया, इसके लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको विश्वासपूर्वक बताना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकता है– गांव की ओर चलें, जंगल की ओर चलें। चाहे ट्राइबल है, socially-economically backward है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, अब ऐसे किसी भी व्यक्ति को या वहां के यंग लड़कों को रोजगार के लिए अब दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब यहां बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे खादी ग्रामोद्योग ने बहुत अच्छा काम किया। आपके बारामूला जिले में आतंकवाद से प्रभावित काफी बड़ा क्षेत्र है। वहां की महिलाओं को हमने रुमाल बनाने का काम दिया। मेरी जानकारी में है कि अभी वहां 2,000 महिलाएं काम कर रही हैं और वे रुमाल बना रही हैं। गुलाम नबी साहब, यह एक रुमाल केवल 50 ₹ का है। दो करोड़ रुमाल पेटीएम ने खरीद लिए और अब हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। ऐसे तीन रुमालों की कीमत 150 ₹ है, जबकि मार्केट में जो ब्रांडेड रुमाल है, उसकी कीमत 350 ₹ है और कंपनी के रुमाल की कीमत 250 ₹ है। अभी वहां 2,000 महिलाएं रुमाल बना रही हैं। अभी तक यह हुआ नहीं है, लेकिन मैं इस रुमाल को एक्सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। इसकी क्वॉलिटी अच्छी है और यह रुमाल 50 ₹ का एक है। इस प्रकार, यह सस्ता भी है। वह क्षेत्र, जो आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र था, वहां 2,000 महिलाएं यह काम कर रही हैं। उनको पहले प्रति रुमाल दो ₹ की मजदूरी मिलती थी। वे 80 रुमाल रोज बनाती थीं, तो उनको 160 ₹ मिलते थे। हमारे खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष ने कहा कि मैंने लॉचिंग की है, तो मैंने कहा कि दो ₹ में क्या होता है, आप अपना प्रॉफिट कम कीजिए, पर उनको तीन ₹ प्रति रुमाल दीजिए। अब तीन ₹ प्रति रुमाल के हिसाब से एक महिला को 240 ₹ मिल रहे हैं। इस तरह आज उन महिलाओं को रोजगार मिला है।

मैं आपको बताता हूं कि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई है, तो वह यह है कि हमारी जितनी योजनाएं हैं, उनके बारे में हमारे कम्युनिकेशन में काफी कमी है। हमारे पार्लियामेंट के मेम्बर्स को भी हमारी सारी योजनाओं के बारे में मालूम नहीं है। उनकी तो छोड़ दीजिए, मैं भी रोज़-रोज़ पढ़ता हूं, तब भी मुझे पूरी डिटेल मालूम नहीं होती हैं। मुझे भी पूरी डिटेल मालूम नहीं है, ऐसी स्थिति है। इसलिए मैंने डिपार्टमेंट से कहा कि हम सभी माननीय संसद सदस्यों को बुलाएंगे और उनके सामने हम अपनी योजनाओं का presentation करेंगे। हमने ऐसा तय किया था, लेकिन अभी उसको हमने postpone किया है। मैं अपना एक छोटा-सा एग्जाम्पल बताऊंगा, जो बहुत सक्सेसफुल है। मैंने तय किया कि मैं अपने लोक सभा क्षेत्र में 50,000 लोगों को रोजगार दूंगा, इसलिए मैं पांच साल से इसके पीछे पड़ा हूं। मेरे पास नामों की एक लिस्ट है कि मैंने 33,280 लोगों को रोजगार दिया। अब मेरा प्रयास यह है कि मैं यह संख्या 50,000 पूरी करूंगा। इसके लिए मैंने पूरे विदर्भ के एमएलएज़ और एमपीज़ की मीटिंग बुलाई है। हमारे यहां मराठी में संसद सदस्य को खासदार कहते हैं। पहले हमने "खासदार क्रीड़ा महोत्सव" आयोजित किया। वह महोत्सव 20 दिन चला। उसमें कम-से-कम 52,000 प्लेयर्स ने भाग लिया, 32 गेम्स आयोजित हुए और 110 स्टेडियम्स में लोगों ने खेला। वहां श्री सचिन तेंदुलकर वगैरह आए और वह एक काफी बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद, वहां "सांस्कृतिक महोत्सव" हुआ। फिर मैंने कहा कि केवल रोड और bridges बनाने से विकास नहीं होता। अब मैंने उद्योग महोत्सव आयोजित किया। आप उसको "सांसद उद्योग महोत्सव" कह सकते हैं, लेकिन हम लोग मराठी में उसको "खासदार उद्योग महोत्सव" कह रहे थे। आप सब लोग यह कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ हैं। हमारा विज़न कितना कमजोर है, यह मैं बताता हूं। मैंने यह जो घड़ी पहनी हुई है, इसको टाइटन ने बनाया है। इसकी बेल्ट खादी की है, इसका डायल खादी का है और यह काफी सुंदर भी है। यह लेडीज़ के लिए भी है और जेन्ट्स के लिए भी है। हमने जितनी घड़ियां बनाईं, उतनी मार्केट में चली गईं। ...**(व्यवधान)**...

**श्री मो. नदीमुल हक** (पश्चिमी बंगाल): सर, अगर आप एक-एक घड़ी हमें भी प्रेजेंट कर देते, तो हम लोग भी उसे पहन पाते। ...**(व्यवधान)**...

†**جناب محمد ندیم الحق:** سر، اگر آپ ایک ایک گھڑی ہمیں بھی پریزینٹ کردیتے، تو ہم لوگ بھی اسے پہن پاتے ---(مداخلت)---

**कुछ माननीय सदस्य:** हम लोग भी उसको खरीद लेते। ...**(व्यवधान)**...

**श्री नितिन जयराम गडकरी:** सर, सबको free of charge देना तो मुश्किल है, पर मैंने अपने अध्यक्ष महोदय को दिया तथा लोक सभा के स्पीकर को दिया। हमने कुछ प्रमुख लोगों को दिया है। मैं विपक्ष के नेता को जरूर एक घड़ी दे दूंगा। मैं आप लोगों से कहूंगा

†Transliteration in Urdu Script.

[श्री नितिन जयराम गडकरी]

कि आप लोगों के लिए मैं डिस्काउंट देकर इसके मिलने की व्यवस्था करा सकता हूं। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो खादी ग्रामोद्योग की बात हुई, वे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमको इसको नए विज़न में कॉमर्शियली कॉरपोरेट में लाना पड़ेगा, तभी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जो जयराम जी कह रहे थे, वह बिल्कुल सही है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। हमारा टर्नओवर अभी साढ़े तीन हज़ार करोड़ ₹ तक जाएगा। विलेज इंडस्ट्री का पिछले साल का टर्नओवर तकरीबन 75 हज़ार करोड़ ₹ का हुआ है, इस साल का एक लाख करोड़ ₹ होगा और हमारा प्रयास है कि पांच साल में ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि वह कम-से-कम पांच लाख करोड़ ₹ तक जाएगा। महोदय, खादी ने एक डेनिम बनाया। मुझे ये पत्रकार लोग व अन्य बहुत लोग जीन्स की पैंट पहने हुए दिखते हैं, मैं सबसे पूछता हूं कि आप खादी डेनिम यूज़ क्यों नहीं करते हैं? यह जो अमेरिकन कंपनी है, लिवाइस या अन्य कोई नाम है, वह हमारा पूरा खादी डेनिम का कपड़ा खरीद रही है। उनकी ब्रांडिंग होने के बाद हमारे ही लोग उसे 3-4 हज़ार ₹ में खरीदते हैं और हमारे यहां सिलाई होने के बाद 5-7 सौ ₹ में मिले तो उसकी कीमत नहीं मिलती, क्योंकि मार्केटिंग के लिए सोचना होगा तो बहुत अच्छा काम होगा। मैंने बीच में डिज़ाइनर्स की भी मीटिंग की थी, इसमें बहुत potential है। मैं हमारी महिला सदस्यों के लिए विशेष रूप से दो अच्छी बातें बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने एक करोड़ लोग जो साइकिल रिक्शा चलाते थे, उनके बारे में बताया। वैसे ही एक सोलर चरखा है, यह महात्मा गांधी रिसर्च विज्ञान इंस्टीट्यूट, वर्धा ने बनाया है। जब कलराज मिश्र जी मंत्री थे, गिरिराज जी मंत्री थे, तब मैं उनके पीछे लगा। अब यह सोलर चरखा बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। अभी स्मृति इरानी जी और मेरे बीच में मीटिंग हुई, मैंने उनको कहा कि आपका 25 परसेंट जो सूत लगता है, वह आप सोलर चरखे से खरीदिए। उन्होंने यह प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया और हमने यह योजना बनाई है कि पांच साल में हम 10 लाख महिलाओं को, एक-एक महिला को दो सोलर चरखे देंगे और उस चरखे से जो सूत निकलेगा, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं, उन सबने जो कपड़ा पहना हुआ है, उससे अच्छी क्वालिटी का सूत कपड़े के लिए वहां बनता है।

हमने जो स्फूर्ति योजना बनायी है, उसमें हमने एक योजना में जो 13 प्रोजेक्ट्स मंज़ूर किए, उनमें दो हज़ार सोलर चरखे महिलाओं को मिलते हैं, 40 करोड़ रुपये की स्कीम है, हम उसमें 10 करोड़ रुपये incentive दे रहे हैं और उसमें एक प्रोजेक्ट के पीछे साढ़े तीन हज़ार लोगों को रोज़गार मिल रहा है और मैंने बड़े-बड़े पैंटालून जैसे लोगों से कहा कि आप इसमें आइए, वे आने के लिए भी तैयार हैं कि कपास, सूत से लेकर weaving आदि सब सोलर पर होगा। साइज़िंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग आदि जैसे 13 प्रोजेक्ट्स शुरू भी हो गए हैं। उसका जो कपड़ा होगा, उसकी डिज़ाइनिंग होगी और उसके बाद उसका

**4.00 P.M.**

एक्सपोर्ट होगा। हमारे देश में किसानों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। जहां कपास होती है, वहां यह हो सकता है। ग्रामीण और विशेष रूप से ट्राइबल और 115 Aspirant Districts को केन्द्र बिन्दु मानकर हमने अनेक योजनाएं बनायी हैं।

आपने कॉयर की बात की है। हमारी आईआईटी के साथ मीटिंग हुई, उसमें आदरणीय राज्य मंत्री जी थे। हमने आईआईटी चेन्नई को अपॉइंट किया और अभी embankment में आपको यह मालूम होगा कि हाइड्रोपॉनिक्स, जो पानी पर खेती हो रही है, वह बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। उसमें जो पिट लगता है, वह कॉयर का होता है। यह कॉयर का जो बोर्ड हमारे केरल का है, इसका टर्नओवर 1,900 करोड़ ₹ से 3,300 करोड़ ₹ हुआ है। वे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसमें अभी खेती से लेकर कॉयर को बहुत डेवलप करने की आवश्यकता है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि में कर सकते हैं।

मैं आपको बताता हूं कि बंगाल से जूट और कॉटन मिलाकर एक जैकेट आया है, परसों मैंने पार्लियामेंट में पहनी, वह बहुत सुंदर कपड़ा है, इतने अच्छे-अच्छे combinations बन रहे हैं कि आवश्यकता है कि इसकी ठीक प्रकार से मार्केटिंग की जाए। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के सांसद बोल रहे थे, इन्होंने मैटल क्राफ्ट बनाया, आप आज छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा मैटल क्राफ्ट बनता है, बहुत सी जगह पर जैसे बनारस के सिल्क की बात होती है। इन सभी बातों को लेने के लिए कॉमर्शियली एक योजना बनायी है, पर मुझे याद है कि मुझे एक अच्छा अनुभव मिला। जब मैं शिपिंग मंत्री बना तो मैंने एक बहुत बड़ी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की एजेंसी को अपॉइंट किया था कि आप हमारे पोर्ट का अध्ययन करके इसका बिज़नेस, efficiency, टाइम आदि बढ़ाने के लिए मुझे रिपोर्ट दीजिए। उन्होंने 120 रिकमंडेशंस दिए और 120 रिकमंडेशंस में मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं था। मैंने अपने डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि इसको implement कीजिए, मुझे यह चाहिए। आपको ताज्जुब होगा कि हमने 103 implementation योजनाएं पूरी की।

और आश्चर्य होगा कि हमारे पोर्ट सेक्टर का प्रॉफिट 7 हज़ार करोड़ रुपये हुआ। जयराम जी, खादी ग्रामोद्योग के बारे में आप और बाकी सब लोग मिलकर डिटेल में और सुझाव दीजिए। खादी ग्रामोद्योग का टर्नओवर केवल साढ़े तीन हजार या चार हजार करोड़ से नहीं होगा। इसको 25 हजार करोड़ के ऊपर ले जाना है। इसमें Handloom, Handcrafts और Honey है। अभी मैं honey के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि Honey Cluster बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि Amazon की site पर जो जम्मू-कश्मीर में, उत्तराखंड में और हिमाचल में high altitude पर honey है, उसकी कीमत 5,000 ₹ किलो है और हमारे यहां 200 ₹ किलो भाव है। हमने honey का cube बनाया, अभी honey का ऐसा सिस्टम आया है। मैंने कैबिनेट की मीटिंग के बाद तुरंत प्रधान मंत्री को चाय के लिए आमंत्रित किया और

[श्री नितिन जयराम गडकरी]

चाय में honey को मिलाया। फिर मैंने उनसे कहा कि आप "मन की बात" के द्वारा इस बात का प्रचार कीजिए कि आप शुगर नहीं, चाय, कॉफी में honey लीजिए। उन्होंने हंसते हुए मुझसे कहा कि आज आप मुझे कह रहे हैं कि honey लो और फिर शुगर वालों को तकलीफ होगी, तो फिर मेरे पास आओगे कि शुगर मार्किट का क्या होगा? मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि फिशिंग, बैम्बू और उसके साथ सबसे important चीज़ है कि हमारे जंगल में, हमारे ट्राइबल सेक्टर में, जो हमने अभी हाथ में लिया है, रतनजोत, मोह, साल, करंज और टोली है। Jatropha oil से हमारे petroleum institute ने aviation fuel बनाया। पिछली 26 जनवरी को हमारे हेलीकॉप्टर और एयर फोर्स के हमारे फाइटर जेट 100 परसेंट bio aviation fuel से चले। फिर हम Spice Jet का एक plane देहरादून से दिल्ली 25 परसेंट इस पर लाए और 40 हजार करोड़ का हम लोग import कर रहे हैं। हमारे जंगल में हमारे वनवासी अगर bio aviation fuel बनाएंगे, तो कितने वनवासियों को रोजगार मिलेगा। हमने bio-technology का उपयोग करके, bio aviation fuel, tribal sector में 115 Aspirational Districts में कैसे बनाएं, तो हमने उस काम की शुरुआत की है।

सर, मुझे दुख होता है, जब भी सुबह मैं अखबार पढ़ता हूं, तो एक भी अखबार का कागज इंडियन नहीं हैं, सब imported हैं। हमने हमारे पेपर मिल बंद कर दिए। हमारे जंगल में आज कनाडा से और हमारे साउथ अफ्रीका से ट्रक भर-भर के 40 हजार करोड़ का पेपर पल्प आता है, 40 हजार करोड़ का पेपर आता है, 20-25 हजार करोड़ की लकड़ी आती है। हमारे यहां वेस्ट लैंड पड़ी हुई है। मैं clean environment का समर्थक हूं। हमारे मोहन धारिया जी, जो महाराष्ट्र के हैं, अभी हमारे यहां केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने वेस्ट लैंड पर उपयोग करके एक सुंदर रिपोर्ट भारत सरकार को दी थी। उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि पेपर मिल में हम यहां पल्प तैयार करेंगे। हमारी जो वेस्ट लैंड है, वहां पेड़ लगाएंगे। बैम्बू के बारे में यह अनुभव आया कि बैम्बू को कटिंग करने की परमिशन नहीं थी। मैंने एक दिन Forest Secretary से पूछा कि बैम्बू Grass है या Tree है। तब उन्होंने कहा कि यह Grass है। मैंने फिर उनको आगे पूछा कि क्या Grass काटने की परमिशन की आवश्यकता है? वे बोले नहीं है। मैंने उनसे बोला कि इतने सालों से आप बैम्बू काटने के लिए restrict क्यों करते हो? क्या कारण है, कौन-से कायदे पर करते हो? वे चुप बैठ गए। मैं प्रधान मंत्री के पास गया और हमारी सरकार पहली सरकार है और मोदी जी हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं, मैंने उनसे इस बारे में बात की, तब हमने बैम्बू को grass मानकर तोड़ने की अनुमति दी। चाइना में बैम्बू की इकोनॉमी 50 हज़ार करोड़ की है। बैम्बू से अचार बनता है, बैम्बू से कपड़ा बनता है, बैम्बू से फर्नीचर बनता है, बैम्बू कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, अगरबत्ती की काड़िया बनती हैं, बैम्बू से कितनी चीज़ें बनती हैं और हम ऐसे clean environment में ऐसी extreme स्थिति पर चले गए कि बैम्बू नहीं तोड़ना। अब

मैंने किसानों को कहा कि हमारे यहां बैम्बू लगाओ। अब बैम्बू से Bio-CNG तैयार हो रहा है। आप environment के लिए इसे जरूर support कीजिए। यह जो पराली है, वह दिल्ली के पास के क्षेत्र में जलाते हैं। पराली से Bio-CNG develop करने की technology आ गई है। अब एक प्लांट लुधियाना में लग रहा है। मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा कि हम लोग गांव में ऐसे हज़ारों प्लांट लगाएंगे, ताकि हमारे गांव के किसानों को, वहां के ट्राइबल लोगों को रोजगार मिले, तो पहली बात तो यह है कि आप सब लोगों ने जो कहा, वह बिल्कुल सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, वनवासी क्षेत्र के लिए और 115 Aspirational Districts के लिए अलग सोचना होगा, अलग techonology लानी होगी, वहां अलग रोजगार खड़ा करना होगा और वहां का Per-Capita Income GDP और Growth Rate बढ़ाना होगा, तब ही हिन्दुस्तान का विकास हो सकता है। प्रधान मंत्री जी ने पहली बार इस प्रॉब्लम को 115 Aspirational Districts को निकालकर इसके लिए priority देने का निर्णय किया है। काम कठिन है, लेकिन हमने इसको priority दी है और खादी ग्रामोद्योग के द्वारा यह village industry का turnover बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में और ट्राइबल सेक्टर में techonology ले जाकर रोजगार निर्माण करने का प्रयास यह हमारी प्राथमिकता है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अंदाज़न MSME के 6.3 करोड़ units हैं, 6,000 से 8,000 products हैं और 11 से 12 करोड़ लोगों को हमने इनमें रोज़गार दिया है। मैं मानता हूं कि प्रॉब्लम्स हैं - प्रॉब्लम्स global economy के कारण हैं, प्रॉब्लम्स demand and supply के कारण हैं, प्रॉब्लम्स business cycle के कारण हैं, कुछ प्रॉब्लम्स Coronavirus के कारण हैं, नोटबंदी होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स उभरकर आयी हैं, कुछ GST के बाद आयी थीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह एक temporary phase था। इनसे बाहर निकलने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल ही रिज़र्व बैंक से, MSME sector की जो इंडस्ट्रीज तकलीफ में हैं, उनको restructure करने के लिए मैंने रिपोर्ट ली और 6 लाख - मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि 6 लाख MSME units को हमने restructure कर दिया है। इसके बाद आज निर्णय हुआ - इसके पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में बताया है कि यह मुद्दत 31 मार्च तक थी, अब हमने इस 31 मार्च तक की मुद्दत को 31 दिसम्बर तक बढ़ा दिया है और सब बैंकों को कहा है कि आप इस संबंध में काम करिए। आप जो बात कह रही हैं, वह बहुत नैसर्गिक है - मैं ज्यादा बोल नहीं पाता - यह सच है कि बैंक वाले आसानी से लोन नहीं देते हैं।

**विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद)**: आसानी से नहीं, देते ही नहीं हैं।

**श्री नितिन जयराम गडकरी**: वही मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं और आज मैं आपकी मदद चाहूंगा। मैंने और निर्मला सीतारमण जी ने अशोका होटल में सभी बैंकों के चेयरमैन के साथ मीटिंग की। मैंने एजेंडा बनाकर उन्हें दिया। जब पहले मुझे बोलने के लिए कहा गया तो मैंने कहा कि आपके बैंक का इतना टारगेट है - मेरे पास सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ

[श्री नितिन जयराम गडकरी]

है - तो एक बैंक ने कहा कि हमने टारगेट पूरा किया है। मैंने उनसे पूछा कि आपको टारगेट किसने बताया? आप target के पीछे 'minimum' शब्द लगा दीजिए और 'minimum target' कर दीजिए। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, मेरे पास इसका पूरा data है - आप मेरे ऑफिस में आइए, मैं दस दिन के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन से बैंक में कितनी एप्लीकेंशस receive हुईं, कितने का लोन मंज़ूर हुआ और किसका क्यों नहीं हुआ, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। 22 टका लोगों को लोन ही नहीं दिया गया था। जब मैंने बैंकों के चेयरमैन से पूछा कि आपने लोन क्यों नहीं दिया तो उन्होंने कहा, "There are problems; they are out of area." तो मैंने कहा कि अगर वे out of area हैं तो वह application जिस एरिया के बैंक की है, उसको transfer कीजिए, आपने transfer क्यों नहीं की? तब उन्होंने कहा कि application is incomplete. मैंने कहा कि अगर उसने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया तो उसे बुलाइए, उससे सर्टिफिकेट लीजिए और उसे पूरा कीजिए। अब बैंक वालों को यह पता चल गया। यह पूरा data मेरे पास है कि पूरे देश में भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, Pradhan Mantri Employment Generation Programme से लेकर अन्य सारी योजनाओं का software मेरे ऑफिस में आया है। दस दिन के अंदर इसकी मॉनिटरिंग हुई है और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बहुत strictly कहा है कि यह होने ही चाहिए। अभी मेरे पास जानकारी है कि 22 हज़ार लोगों को उन्होंने तुरंत लोन मंज़ूर कर दिया है। इस प्रकार अब बड़ी संख्या में उन्हें लोन मिलेगा और यह data district-wise, branch-wise होगा। अब इसमें एक और प्रॉब्लम यह थी कि यह केवल Scheduled Banks को दिया गया था। फिर मैंने उनसे यह पूछा, "Why Scheduled Banks; why not Cooperative Banks,; why not Urban Cooperative Banks; why not NBFCs?" तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अभी तक यह सोचा नहीं है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने यह ऑर्डर निकाला है, हमारे महाराष्ट्र में Urban Cooperative Bank कितना बड़ा है, गुजरात में कितना बड़ा है - अब इसके बाद MSME की सारी स्कीम्स के लिए Urban Cooperative Bank, District Cooperative Bank, NBFC से लेकर सबको permission दे दी गयी है। अब कोई भी NBFC, कोई भी बैंक फाइनेंस कर सकता है, जिसके कारण अब देने वालों की संख्या बढ़ गयी है और इस टारगेट को पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। इसमें important चीज़ यह है - आपमें से बहुत से लोगों ने यह कहा कि आपका बजट कम हुआ है - आपको यह पता है कि बैंक जो लोन देते हैं, मुझे भी लगता था कि बैंक एहसान कर रहे हैं कि वे लोन दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस सेक्टर में एक लाख करोड़ का लोन बैंक देता है तो 75 हज़ार करोड़ का insurance हम करते हैं। 1.5 परसेंट भरकर हम उस amount का 75 परसेंट insurance cover करते हैं और हमारे पास 10 हज़ार करोड़ का Corpus है।

आपने कहा था कि बजट कम दिया, मैं बताना चाहता हूं कि corpus में पैसा है। जो लोग पैसे नहीं देते हैं, हम उनको corpus से निकाल देते हैं, इसलिए हमने 75 परसेंट amount की गारंटी ली है और बैंक केवल 25 परसेंट के ही collateral मांग सकता है। कुछ तो ऐसी योजना है, जिसमें Scheduled Castes, Scheduled Tribes, hilly areas और अरुणाचल और कश्मीर वगैरह के लिए हम 100 परसेंट गारंटी लेते हैं। कोई बैंक ऐसा नहीं है कि वह दे रहा है, अगर उनके पैसे डूब जाएंगे, तो हमने उनको insure किया है और हम उनके पैसे उनको वापस कर रहे हैं। पूरी योजना में भारत सरकार का सपोर्ट है। बैंकों को इसमें कहा कि हमने कोई कटौती नहीं की है। 2015-16 में 2,620 करोड़ ₹ का बजट था। 2018-19 में 6,552 करोड़ और 2019-20 के लिए बजट बढ़कर 7,011 हो गया। Subsidy disbursed, 2015-16 में 1,020 करोड़ दी और 2018-19 में 2,070 करोड़ दी और इस साल 1,661 करोड़ दी है। इसमें मार्च का पूरा आंकड़ा नहीं आया है। Units set up, 2015-16 में 44,340 यूनिट्स सेट अप हुए, 2018-19 में 73,427 यूनिट्स सेट अप हुए और आज तक 55,737 यूनिट्स सेट अप हुए हैं। Employment 2015-16 में 3,23,362 थी, 2018-19 में 5,87,416 थी और अभी तक 4,45,896 हुई है। Credit guarantee extended, जिसके बारे में मैंने अभी बात की है, जो हम गारंटी देते हैं। हमने insure किया है, हमारा दस हजार का corpus है और बैंक का कर्जा डूबता है, तो भारत सरकार पैसा भरती है। ऐसा नहीं है कि यह popular है, इसे बंटवा दो। हां, यह बात जरूर है कि जो कोई fraud करने वाले हैं, किसी की अलग तरह की intentions हैं, तो उसके बारे में हम नहीं कहेंगे कि उनको दो। उनके रिकॉर्ड्स ठीक से चैक करने चाहिए। Credit Guarantee extended, यह 2015-16 में करीब 20 हजार करोड़ था, फिर यह 2018-19 में 30,168 करोड़ हुआ और अभी मार्च से पहले 35,456 करोड़ हुआ और यह मार्च एंड तक 45 हजार करोड़ जाएगा। Cluster Development MSMEs के बारे में कहा गया और SFURTI के बारे में सही कहा गया। Cluster approved - 2015-16 में 34 हुए, 2018-19 में 98 हुए और इस साल 376 हुए। मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आपके संसदीय क्षेत्र में handloom, handicraft, जो भी आप चाहते हो, जो भी वहां की कला है, आप उसका cluster तैयार करिए। अगर आपके 500 worker होंगे, तो हम लोग पांच करोड़ रुपये तक की subsidy देते हैं और अगर उससे कम होगा, तो ढाई करोड़ देते हैं। आप पूरे कारीगरों को निकालकर अलग-अलग क्लस्टर में आइए, हम पूरी तरह से मदद करेंगे। यह जो credit subsidy है, जिसमें हम 15 per cent of loan amount देते हैं, units assisted, यह 2015-16 में 5,047 था, 2018-19 में 14,155 यूनिट्स था और अभी इसका data मेरे पास नहीं है, पर वह 20 हजार तक जाएगा। खादी की सेल भी बहुत बढ़ रही है। मुझे अन्यथा मत लीजिए, अब जो modern लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, यहां पर जया जी भी बैठी हैं, अन्य लोग हैं, अलग-अलग प्रकार के लोग fashion designing में हैं, वे अब खादी का उपयोग कर रहे हैं। इतने सुंदर डिजाइन्स बने हुए हैं कि अब लोग इसे prefer कर रहे हैं। प्रॉब्लम है कि हमारा commercial, professional

[श्री नितिन जयराम गडकरी]

marketing system नहीं है। मैंने डिजाइनर की मीटिंग ली, तो खादी ग्रामोद्योग ने कहा कि हम सबको... मैंने कहा कि तुम्हारा काम नहीं है, जिसका बंदर वही नचाए, आप इस लफड़े में मत पड़िए। आप Bank of Designs करके खोल दीजिए। डिजाइन्स वेबसाइट्स में कीजिए और जो छोटा आदमी लेगा, वह जो डिजाइन सलेक्ट करेगा, उसकी royalty उसके account में डायरेक्ट जमा कीजिए। आप इसको हाथ मत लगाइए। मेरा प्रामाणिक मत है कि हम facilitator हैं, हम businessman नहीं हैं। हमने घड़ी टाइटन से बनाई, हमने बाजार से नहीं बनाई, वह टाइटन ने अपनी बनाई है। हर जगह पर हमारा प्रयास यही है कि उसमें branding हो और branding होने के बाद इन सब चीज़ों की marketing करने के लिए और हम लोग देश में एक नेटवर्क करने के लिए private agency को ही engage करना चाहते हैं। इसमें जैसा आपने कहा कि corporate culture लाना चाहिए, इसकी product designing अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रेट रीज़नेबल होने चाहिए। हनी से लेकर कपड़े तक, हैंडलूम से लेकर हैंडिक्राफ्ट तक काफी बड़ा मार्केट मिलेगा। पिछले साल 3,215 करोड़ का टर्नओवर हुआ, मार्च end तक यह इस साल 2,714 करोड़ हुआ और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से साल के अंत तक यह साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये से ऊपर जाएगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर है, वह 2015-16 में 40,384 करोड़ था और पिछले साल 71,076 करोड़ था और इस साल 60,343 करोड़ है। आपकी बात में थोड़ा दम है, there are challenges. मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपकी कोई अच्छी बात है, तो उसे accept करूंगा और अगर कोई कमी होगी तो उसे आपसे सलाह लेकर सुधारूंगा। अब 60,343 करोड़ हुआ है, इसमें अभी मार्च का भी ऐड होना है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक्सपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं। मैं मुम्बई के एक एक्सपोर्ट के कार्यक्रम में था। वहां पर मैंने सात महिलाओं को अवाड्र्स दिए। एक यंग महिला, जो करीब 30 साल की होगी, मैंने उससे पूछा कि आप क्या करती हो, तो उसने बताया कि मैं onion एक्सपोर्ट करती हूं। मैंने उससे पूछा कि टर्नओवर कितना है? उसने साढ़े पांच सौ करोड़ का टर्नओवर बताया। एक दूसरी महिला को मैंने अवार्ड दिया और उससे पूछा कि आप क्या करती हो, तो उसने बताया कि मैं जूती बनाती हूं। मैंने पूछा कि एक्सपोर्ट कितना है, तो उसने बताया कि 900 करोड़ का है। आपने जो खादी ग्रामोद्योग की डेफिनेशन बताई है, इसके बारे में वाद-विवाद था। इसमें इन्वेस्टमेंट, बाद में मशीनरी की cost और employment कितना दिया, इन तीनों बातों पर जोर था। हमने इसके बारे में पूरी पंचायत की। देश भर की इंडस्ट्री एसोसिएशन्स और सभी के सजेशन्स हमने ले लिए। उसके बाद पॉलिसी फाइनल की और मेरे साइन हो गए। मैं आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी के पीछे लगा, फिर उन्होंने साइन करके दे दिया, कानून मेरे पास आया। वह एक बार प्रधान मंत्री

जी को देना होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अधिवेशन समाप्त होने के पहले MSME की नई डेफिनेशन आएगी और निश्चित रूप से यह सबको फायदा पहुंचाने वाली होगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट सपोर्ट है और इसको प्रधान मंत्री जी ने काफी सपोर्ट किया था। पहले यह हमारा 12,565 करोड़ था, वह पिछले साल 4,376.64 करोड़ हुआ और इस साल 33,210 करोड़ हुआ है। इसमें से तीन परसेंट महिला इंटरप्रेन्योर्स को मिला है यानी महिलाओं को भी priority मिली है। परन्तु जो बात आपने कही है, वह सच है। समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ऐसी कहावत है। यहां पर भी प्रॉब्लम यही है, चाहे गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट के अलग-अलग प्रकार के प्रतिष्ठान हों, पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ हों, सभी उनसे माल खरीद लेते हैं, लेकिन पैसे नहीं देते हैं और तीन-तीन, चार-चार महीने तक नहीं देते हैं। सब MSME इसमें समाप्त होने के कगार पर खड़े हैं, सब लोग बरबाद होने के कगार पर खड़े हैं। अब यह प्रॉब्लम ऐसी है, इसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। देश की और उद्योगों की स्थिति ऐसी है। कानून पास करना तो बड़ा आसान है। अगर पेमेंट तीन महीने नहीं दी, तो इतना ब्याज लगाओ, अगर पेमेंट नहीं दी, तो एम.डी. को इतने दिन की जेल दे दी, कार्रवाई उनके खिलाफ करो। परन्तु उनकी भी प्रॉब्लम्स उसी तरह की हैं। इसीलिए हमने एक समाधान पोर्टल निकाला है। मुझे हमारे सेक्रेटरी कहते थे कि हमने इतने लोगों का निपटारा किया। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे यह सब मत बताओ। मैं गांव में घूमता हूं। हर आदमी बताता है कि मेरे पैसे नहीं दिए। अब तुम समाधान-समाधान बोलते हो, लेकिन इस समाधान से मेरा कोई समाधान नहीं निकल रहा है। करीब 20-22 हजार केसेज़ हैं, आपने करीब 25 हजार करोड़ का काम किया। मेरे अंदाज़ से स्माल स्केल इंडस्ट्री का पैसा जो बड़े उद्योगपति, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स के पास जो अमाउंट लटका हुआ है, वह साढ़े पांच लाख से छह लाख करोड़ तक है। आदरणीय विधि मंत्री, आईटी मंत्री हैं। बीएसएनएल के लोगों का पैसा देना, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैं और फाइनेंस मिनिस्टर उस कमेटी में हैं। मैं एनएचएआई के कांट्रेक्टर को बोलता हूं कि तुम पैसा लेकर जा रहे हो, तुम बताओ कि तुमने छोटे लोगों के पैसे दिए क्या? वह बताता है कि NCLT में हैं। मैंने कहा कि मैं NCLT नहीं मानता। जब तक तुम छोटे-छोटे लोगों की, दस-दस, बीस-बीस लाख ₹ की liability नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हारे पैसे नहीं देता। यह ऑर्डर हमने उनको बता दिया है। वे पैसे ले जाकर किसको देते हैं, वे पहले बड़े आदमी को देते हैं, पहले पैसा बैंक में देते हैं, लेकिन जो साइट पर ठोक-पीट करके काम कर रहा है, अपने जीवन की पूंजी 10-20 लाख ₹ लगाकर काम कर रहा है, उसको ज़ीरो पैसा मिलता है। प्रामाणिकता से यह प्रश्न गंभीर है और इस पर मेरे पास अभी तक कोई ठीक जवाब नहीं है, न मेरे किए कार्य से पूर्ण समाधानी होगी, क्योंकि इसके दोनों ही बाजू हैं। हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठे हैं और इसके लिए कोई न कोई समाधान निकालेंगे। यह बात बिल्कुल सही

[श्री नितिन जयराम गडकरी]

है कि MSME के सेक्टर के लोगों को यदि यशस्वी करना हो, तो उनका पेमेंट अधिक से अधिक तीन महीने के अंदर उनको देना ही पड़ेगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर वह पैसा मिलेगा, तो यह सैक्टर बहुत आगे जाएगा और अगर पैसा नहीं मिलेगा, तो जो छोटे-छोटे लोग हैं, वे बहुत मुश्किल में आएंगे। आप सबने इस बात को कहा है, मैं इस बारे में गंभीर नोट लेकर जरूर काम करूंगा।

महोदय, टेक्नोलॉजी सेंटर्स के बारे में भी हमने काफी बड़े प्रमाण में काम किया है। इसमें हमने 400 सेंटर्स खोलने के लिए लगभग 5,000 करोड़ ₹ का प्रोविजन किया है।

**श्री जयराम रमेश:** उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री को सुझाव है कि जो MSME है, उसका जो outstanding invoice है, यदि वह 1 करोड़ ₹ से ऊपर है, तो उसे आप वेबसाइट पर डालिए, नेम और शेम करिए। इससे यह भी पता लगेगा कि कौन सी कंपनी सही वक्त पर पेमेंट नहीं कर रही है, यह कानूनी तौर से कीजिए और आप एक्ट में ऐसी अमेंडमेंट लाइए। आज लार्ज कंपनीज़ को Insolvency and Bankruptcy Code के तहत upload करना पड़ता है। आप MSME को कहिए कि जहां आपका outstanding 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो, जो कोई भी हो, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उनके नाम आप मेंडेटरिली वेबसाइट पर डालिए, ताकि बैंकों को भी पता चले कि delayed payment का कारण क्या है। आज MSME के लिए यह मेंडेटरी नहीं है, इसलिए वे इसे वेबसाइट पर नहीं डालती हैं। लार्ज कंपनीज़ के लिए मेंडेटरी है।

SHRI P. BHATTACHARYA: There is another point, hon. Minister. We have seen that many banks do not pay the full amount to MSMEs, they make just half payments and the remaining is kept pending. Can you give clear instructions to all the banks that whatever amount is granted to MSMEs is paid in full to them? Otherwise, MSMEs would be in big trouble.

**सुश्री दोला सेन:** उपासभाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया, जो सुनने में बहुत अच्छा लगा। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमें लगा कि subjective wish के साथ objective reality का बहुत अंतर होता है। इस अंतर को कैसे सम्हालेंगे? आपने budget crunch पर बोलते हुए बताया कि आपके पास 10,000 करोड़ ₹ का corpus fund है, लेकिन मैं PF Board and ESI Board में मेम्बर हूं, इसलिए मुझे पता है कि PF Board and ESI Board का 1 लाख हजार करोड़ ₹ का corpus fund है, लेकिन जो closed and sick industries हैं, अगर मैनेजमेंट उनको पैसे नहीं दे, तो उनके वर्कर्स मर जाते हैं, लेकिन उस corpus fund से पैसा नहीं दिया जाता है। इसकी पॉलिसी के ऊपर हम Labour Department में चर्चा करते

हैं कि उस corpus fund को हम शेयर बाजार में क्यों लगाएं? वह पैसा तो जो closed and sick industries हैं उन्हीं का है, इसलिए उन्हें क्यों नहीं मिलेगा? हम देखरेख दे रहे हैं इसलिए कि इसी तरह अगर आपका corpus fund होगा, तो MSME की प्रॉब्लम के बारे में जैसे अभी श्री जयराम रमेश जी तथा श्री पि. भट्टाचार्य जी ने बताया और आपने भी बताया कि बैंकों की प्रॉब्लम है, फिर भी आप कह रहे हैं कि तीन महीने में पेमेंट मिलेगी। मैं कहना चाहती हूं कि MSME के बहुत सारे कंसर्न्स हैं, इसलिए उनके लिए तीन महीने भी बहुत ज्यादा हैं। अत: मैं जानना चाहती हूं कि corpus fund को लेकर आपकी क्या पॉलिसी है? आपके पास 10,000 रुपये का अगर corpus fund, तो उसके बारे में भी यदि आप आपका पॉलिसी स्पष्ट रूप से बताएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा।

**श्री नितिन जयराम गडकरी**: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जो corpus fund हमारे पास है, उसकी स्थिति थोड़ी अलग है। हमारा corpus fund trust के अंदर है और वह 10,000 करोड़ रुपये का है और यदि उसमें 2,000 या 3,000 करोड़ रुपये ब्याज के भी जोड़ दिए जाएं, तो इस प्रकार वह लगभग 13,000 करोड़ का हो जाता है। उसमें से हम किसी इंडस्ट्री को फंड नहीं दे सकते हैं। जो बैंक उसे लोन देता है, मान लीजिए किसी बैंक ने किसी इंडस्ट्री को 1 करोड़ रुपये लोन के रूप में दिए, तो उसके 75 लाख रुपये हमने इंश्योर किए और उसके अगेंस्ट हम लोग जो प्रीमियम 1.5 परसेंट भरते हैं, यानी, 1 लाख करोड़ रुपये के लोन के अगेंस्ट हम 1,500 करोड़ रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं और जब बैंक के पैसे किसी इंडस्ट्री में डूबते हैं, तो बैंक हमारे पास आता है, तो ऐसी इंडस्ट्री की 75 परसेंट कॉस्ट हम उस बैंक को इंश्यारेंस के रूप में वापस देते हैं, यह इंडिविजुअल के लिए नहीं है। आप जिस फंड के बारे में बात कर रही हैं, वह लेबर मिनिस्ट्री का फंड है और इस फंड का उपयोग केवल इसी काम के लिए हो सकता है, किसी दूसरे काम के लिए नहीं हो सकता है। उसमें और इसमें थोड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगा।

महोदय, MSME के बारे में जो एक अच्छी बात आप कह रहे थे, मैं उसके बारे में अपको बताना चाहता हूं। मैं National Stock Exchange, मुम्बई गया और वहां 20 MSME में वे कैपिटल मार्केट में गए, तो उस कार्यक्रम में, मुझे वहां के MD ने बताया कि एक MSME है और एक गवर्नमेंट की रेप्युटेड कंपनी है, उदाहरण के लिए मान लीजिए NTPC को उन्होंने माल सप्लाई किया, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे लोगों का जो पेमेंट है, NTPC के नाम पर मार्केट में लगाया। जो साढ़े सात हज़ार करोड़ रुपये की एमएसएमई की पेमेंट थी, उनके अगेंस्ट पैसा खड़ा करके वह पेमेंट करके दी। उन्होंने वह पैसा टेंडर से खड़ा किया, इसलिए उन्हें 7.5 परसेंट ब्याज से पैसा मिला। आप जो U.K. Sinha Committee की बात कर रहे हैं, U.K. Sinha Committee ने हमें पहली बार 10 हज़ार करोड़ रुपये Fund of Funds के लिए दिए हैं। इसमें कल्पना है, थोड़ी technical बात भी है, लेकिन आप लोग

[श्री नितिन जयराम गडकरी]

उसमें थोड़ा-सा सहयोग जरूर कीजिएगा। जैसे मैं एनएचएआई में काम करता हूं, बहुत बार आप लोगों को लगता है कि मैं करोड़ों की बात करता हूं। मैं एक लाख, दो लाख, तीन लाख करोड़ की बात करता हूं, जिससे लोगों को लगता है कि इनका बजट तो 80 हज़ार का है, फिर यह कैसी बात करता है? मैं बजट पर बात नहीं करता हूं, मेरे अलग sources हैं। मैं उन पर पैसा खड़ा करता हूं। अभी ये जो 10 हज़ार करोड़ रुपये हैं, हमने पहली स्कीम यह निकाली है कि जो अच्छी एमएसएमई है, उसके लिए एमएसएमई की financial credit rating and performance credit rating की योजना बनाई है। यह एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी। अप यह समझिए की एक एमएसएमई, जो एक्सपोर्ट अच्छा करती है, यदि वह 50 करोड़ की equity capital market से खड़ी कर रही है, तो उसको 15 परसेंट... 7.5 परसेंट की सहायता हम देंगे। इस तरह से हमने 50 करोड़ में से 7.5 करोड़ दिए। 7.5 करोड़ में हमारी शेयर वैल्यू 10 रुपये है। जब वह मार्किट में अच्छा काम करेगी, तो तीन-चार सालों में 10 रुपये का वह शेयर 70 रुपये का होगा। जो मेरा एमाउंट है, जो 7 करोड़, 50 लाख है, अगर वह 7 परसेंट से 50 करोड़ हो गया ओर जब मैं उसको sale out करूंगा तो मेरे ये जो 10 हज़ार करोड़ रुपये हैं, हमने इनको पांच सालों के अंदर 1 लाख करोड़ रुपये बनाने की योजना बनाई है। हम यह पैसा भी invest करेंगे और फिर नई एमएसएमई को देंगे।

महोदय, U.K. Sinha Committee की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने ही हमें ये 10 हज़ार करोड़ रुपये Fund of Funds तैयार करने के लिए सुझाव दिया था। हमने वह recommend किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी recommend किया और वह अब cabinet के approval के लिए गया हुआ है। अगर यह मिल जाएगा, तो बैंकों में जाने की जरूरत ही नहीं है।

महोदय, हमारी economy की तीन important बातें हैं। ये हैं - pension, insurance and stock exchange. आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, अमेरिका में या किसी और देश में चले जाइए, सबकी पेंशन, इंश्योरेंस, मेडिकल आदि सब उसी में होते हैं। कोई बिल नहीं भरता। हमारे देश में इन तीनों बातों का उतना उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये 10 हज़ार करोड़ रुपये Fund of Funds हैं। जैसे एनएचएआई है, इस साल एनएचएआई में हमारी income 40 हज़ार करोड़ रुपये है। अगले साल मैंने कहा है कि कुछ नहीं, मुझे 5 लाख के 1 करोड़ रुपये करने हैं। अगर बजट को छोड़कर एनएचएआई की साल की income 1 लाख करोड़ रुपये की होगी, तो मैं 10 लाख करोड़ बनाऊंगा। मैं उसको कैपिटल्स करता जाता हूं। अभी यही फाइनेंशियल मॉडल लाया गया है और अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस 10 हज़ार करोड़ को मंजूरी भी दी है। हम लोग पहली बार, जो अच्छी एमएसएमईज़ हैं, उनको National Stock Exchange, Mumbai Stock Exchange या किसी भी Stock Exchange में ले जाएंगे और उनकी मार्किट में जो total equity raise करेंगे, उसमें हम उन्हें 15 परसेंट

**4.30 P.M.**

support करेंगे। आज हम जो 10 रुपये का शेयर लेंगे, एकाध बार यह संभावना भी हो सकता है कि 10 रुपये का शेयर 100 रुपये का होगा और एक दिन 100 रुपये का शेयर 30 रुपये का होगा। सौ में से एकाध बार यह भी होता है, क्योंकि ultimately यह एक प्रकार का चैनल है। मेरा ऐसा विश्वास है कि हम इससे इंडस्ट्री की काफी बड़े परिणाम में मदद कर पाएंगे। अभी एमएसएमई की विशेष रूप से जो सबसे important स्कीम है, वह Prime Minister Employment Generation Programme है। आप इसको अपने डिस्ट्रिक्ट में मॉनिटर कीजिए और इसमें पांच साल में, 2014 से 2019 तक, 2.67 lakh units have been set up providing employment to 21.36 lakh people; providing capital subsidy of 15 per cent in urban areas and 25 per cent in rural areas for micro enterprises for investment up to ₹ 25 lakhs in manufacturing and ₹10 lakhs in services supported by bank loan. ये already हुआ है। अभी करंट ईयर में 58,000 यूनिट्स एप्रूव हुई हैं और हम 1,712 करोड़ की सब्सिडी देंगे। मैंने अभी बैंक की बात बताई है। इस मीटिंग के बाद 22 हज़ार proposals diburse हुए हैं। मैं हवा में बात नहीं करता, इसलिए आप भी मत कीजिए। आप दस दिनों के बाद मेरे पास आइए, मैं आपको पांचों स्कीम्स का Urban Cooperative banks, District Cooperative banks, NBFCs, nationalised banks, Scheduled banks and private banks का सबका रिकॉर्ड, जिसमें किसका लोन मंजूर हुआ, किसका मंजूर नहीं हुआ, इस पूरे रिकॉर्ड का सॉफ्टवेयर मेरे ऑफिस में डेवलप हुआ है। उसको यहां से कंट्रोल करेंगे। इस पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब का अच्छा सपोर्ट मिला है। हम दोनों मिलकर देख रहे हैं। जब हम गारंटी ले रहे हैं और अगर बैंक इस पर लोन नहीं देगा, तो हम उस पर जरूर बोलेंगे कि यह ठीक बात नहीं है, लेकिन फिलहाल बैंक भी हमें cooperate कर रहा है। इसमें काफी अच्छा फायदा हुआ है। मैंने आपको इसमें एक बात बताई थी कि past data analysis has revealed that 11 per cent proposals are getting rejected by banks as target is reached.

उन्होंने कहा कि आप proposal reject कर दीजिए, अभी target reach हुआ है। मैंने कहा, "What is the meaning of target? Your target is minimum target." आप ज्यादा अच्छा काम मत करो, यह किसने कहा है। यह target की limit नहीं है, तो उन्होंने 11 परसेंट और add किया। Second, 11 per cent proposals were rejected as they were out of service area of bank. हमने उनसे कहा कि यह आपके एरिया में नहीं होता, तो जिस एरिया में है, वहां केस transfer करो। Finance Minister की उपस्थिति में 22 per cent pending cases का निर्णय हो गया है। शायद 2-4-5 परसेंट लोग ऐसे निकल सकते हैं, जिन्होंने इसके पहले लोन लिया, वापस नहीं किया, habitual defaulters की लिस्ट में होंगे, तो वह बात छोड़ दीजिए, पर बाकी बैंक में अब pendency निकल जाएगी। इसकी monitoring होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी। 10 दिन के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने

[श्री नितिन जयराम गडकरी]

बैंक हैं, उनका branch-wise record आपको देखने के लिए मिलेगा। मुझे लगता है कि इसमें अड़चन नहीं आएगी।

फिर Credit Guarantee Fund Trust, मैंने already इसके बारे में आपको बताया है। हमने यह भी काफी अच्छी स्कीम की। हम इस साल इसमें बैंकों को 45 हजार करोड़ रुपये देंगे। फिर Micro and Small Cluster Development Programme, यह Common Facility Centre एक अच्छी बात है। For testing, training centres, research and development, effluent treatment, raw material depot, complementing production, etc., to create/upgrade infrastructure facilities in the new/existing industrial areas, इसका काम भी हुआ है। Seventy-six Common Facility Centres have been commissioned which benefit around 85,740 units. Then, 169 infrastructure development projects have been commissioned to benefit around 29,308 units. The Government contributes up to ₹ 18 crore for Common Facility project and up to ₹ 20 crore. Now, the Government contributes up to ₹ 12 crore for common infrastructure projects. यह भी अच्छा चला है।

Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI), इसमें भी village industry में coir, honey, bamboo, bio-fuel, fishing, ये सब लाए गए हैं। इसमें गांवों तक technology ले जाकर काम किया जा रहा है, जिसको मैंने already explain किया। मैं बिल्कुल साफ बताना चाहता हूं कि हमारी दिल्ली में बैठे हुए चाहे कोई भी लोग हों, चाहे politician हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, गांव की आवाज यहां तक नहीं आती है। इसलिए ये village-centric, tribal-centric, Scheduled Caste and Scheduled Tribe-centric, 115 Aspirational Districts-centric, महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय की बात है, the last man of the society, who is socially, economically and educationally backward, उस साइकिल रिक्शा चलाने वाले से लेकर ये 10 लाख सोलर चरखे बांटने वाले तक, इनको केन्द्र बिन्दु मान कर ही यह डिपार्टमेंट आगे जाएगा। इससे urban area में technology आएगी, centres आएंगे, सब कुछ आएंगे।

अभी 53 clusters operational हुए हैं और इस साल 271 हो रहे हैं। अब कुछ negative बातें कहना मेरे लिए ठीक नहीं है, मैंने एक बार पूछा, तो तीन साल में cluster में कुछ हुआ ही नहीं। सेक्रेटरी कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बैठे। मैंने कहा, "Nothing doing; you take the decision." यह मुझे नहीं चाहिए। दूसरा है, "What is the meaning?" आप मुझे बताओ कि क्या यह शुरू हुआ? आपने मंजूर किया, मुझे वह data मत बताओ। क्या वह जमीन पर शुरू हुआ, मुझे वह बताओ। इस data को छोड़ो। आप मुझे अच्छी-अच्छी बातें बता दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। यह क्यों नहीं हुआ, यह

बताओ। अभी उस प्रोजेक्ट में एक mistake थी कि जो land देता है, उसे capital cost में नहीं रखते। मैंने कहा कि यह कैसी बात है! अगर कोई आदमी 20 लाख ₹ की land देता है, he should include it in the capital cost. हमने उसके नियम बदले। हमने बिल्कुल सब नियम बदल दिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आप और बताइए, जहां-जहां आवश्यक होगा, उन सब नियमों के बारे में हम बताएंगे। इसमें जो सबसे अच्छी योजना है, वह यह है कि the Government gives a capital guarantee of ₹ 5 crore for clusters. जैसे यह gun metal वाला cluster है। आप बनाइए। आप 500 कारीगरों को इकट्ठा करिए, cluster बनाइए, मैं आपको 5 करोड़ grant देने के लिए तैयार हूं। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं।

**श्री रवि प्रकाश वर्मा** (उत्तर प्रदेश): सर, मेरी एक जिज्ञासा है। एमपीज़ ने जो गांव adopt किए हैं, क्या उनमें भी clusters बन सकते हैं?

**श्री नितिन जयराम गडकरी**: ये कहीं भी बन सकते हैं। आप लाइए। इस cluster के बनाने से ही जैसा जयराम रमेश जी ने कहा, यह hundred per cent सच है, जब clusters बनेंगे, तब औद्योगिक विकास होगा, जब विकास होगा, तो GDP बढ़ेगा, growth rate बढ़ेगी, employment potential बढ़ेगी और गरीबी दूर होगी। इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। आप इसे लाइए, हम लोग इसके लिए पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हमने सोलर चरखे का काम किया है। मैं Khadi and Village Industry के बारे में एक घोषणा करता हूं कि आने वाले समय में तुरन्त, 15 दिन के अंदर Khadi and Village Industries Commission, KVIC कैसे professionally strengthen करें, इसके लिए हम योजना ला रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जो प्रेज़ेंट अध्यक्ष हैं, शायद मि. सक्सेना हैं, वे काफी एक्टिव हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफी initiative भी ले रहे हैं। अब इसको और professional तरीके से जोड़ कर हम facilitator बनेंगे। इसके लिए एक अच्छी financial consultancy से हम अध्ययन भी करवाएंगे और हमारे सेक्रेटरी की अध्यक्षता में तीन लोगों की कमिटी एपॉइंट करेंगे। इस तरह तीन महीने के अंदर खादी ग्रामोद्योग के Village Industries Commission को हम revamp करेंगे और उसको export-oriented बनाएंगे, ताकि हमारी चीज़ें दुनिया के बाहर भी जाएं। आपके इटावा में भी एक खादी ग्रामोद्योग का एक प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है कि उसे कोई मि. चतुर्वेदी जी चलाते हैं। वे इटावा में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे...**(व्यवधान)**... जी हां, काफी जगह पर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उनको हम लोग पूरी तरह सपोर्ट करेंगे।

Tool rooms के अभी जो सेंटर्स हैं, इनमें Wadhwani Foundation के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। वे अमेरिका से आए हैं, प्रधान मंत्री जी को अमेरिका में वे मिले थे। मैंने हमारे डिपोर्टमेंट को कहा कि तुम किसलिए ट्रेनिंग सैंटर्स चलाते हो, तुम्हारी क्या ताकत है, क्या अनुभव है? जो successfully इस काम को कर रहा है, उसको ट्रेनिंग सेंटर दे दो, तुम ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लफड़े में मत पड़ो। अगर आप ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं,

[श्री नितिन जयराम गडकरी]

तो नौकरी किसलिए करते हैं? आप इस लफड़े में मत पड़ो और जो अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, उनको ये चलाने के लिए दे दो। अब हम लोग ट्रेनिंग देने का काम प्राइवेट सैक्टर को दे रहे हैं और इसकी संख्या काफी बढ़ी है। इसमें 5,000 करोड़ रुपये का प्रोविज़न है। अभी तक इसमें 2,08,174 ट्रेनीज़ से ट्रेनिंग दी गई है। चेन्नई में हमारा एक जूते बनाने की ट्रेनिंग देने वाला एक सैंटर है। आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि उसमें waiting list है। वहां पर एडिमिशन लेने के लिए एक एमपी किसी की सिफारिश लेकर आए और कहा कि इसको वहां appoint कर दो, वह इतना अच्छा सेंटर है। वहां से जूते के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। जूते की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? जूते की इंडस्ट्री 1,48,000 करोड़ रुपये की है, जिसमें से 90,000 करोड़ रुपये की खपत हमारे अपने देश में है और 45,000 से 50,000 करोड़ रुपये का उसका एक्सपोर्ट होता है। इस तरह एक-एक सेक्टर में जो potential है, हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। GST registered MSMEs को हमने 2-per cent interest subvention भी दिया है, जिसमें से 625 करोड़ रुपये disburse भी हुए हैं। इसी तरह गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, एक credit link capital subsidy scheems के तहत MSMEs काफी पड़े परिमाण में, यानी लगभग 34,540 MSMEs को 2,268.80 करोड़ रुपये दिए हैं, for modernisation and technological upgradation. Public procurement policy के बारे में मैंने आपको अभी बताया है।

प्रधान मंत्री जी ने बीच में कहा था कि 59-minutes loan portal होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम भी उनसे सीखते हैं, तो फटाफट लोन सैंक्शन हुए। मैंने आने के बाद banking sector की एक मीटिंग बुलवाई और पूछा कि loan तो sanction हुआ, लेकिन आप यह बताइए कि disbursement कितना हुआ? फिर बाद में समझ में आया कि इसमें और ताकत लगाने की आवश्यकता है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1.88 lakh loans involving ₹ 59,000 crore have been sanctioned and 1.68 loans involving ₹ 50,532 crores have been disbursed. यानी केवल हवा में यह काम नहीं हुआ है। अब एक सीधी बात पूछी जाती है - GST कितना भरते हैं, यह बताओ, बैंक में turnover कितना है, यह बताओ, उसके बाद credit rating हो जाएगी और जिसको triple A rating मिलेगी, उसको तुरन्त red carpet मिलेगा। यह स्कीम अच्छी तरह से चल रही है।

Market access is a problem. चाइना को खड़ा किया Alibaba ने, USA को खड़ा किया Amazon ने और हमको कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारे देश के बजट के बराबर Amazon और Alibaba का turnover है। हमारे देश में मार्केट के बढ़ाने के लिए बीच में मैंने कोशिश की, सरकार में इसकी सलाह, उसकी सलाह करते-करते अब आखिर में मैंने State Bank Capital के साथ बैठकर कहा कि तुम हमारे पार्टनर बन जाओ और मुझे पोर्टल बना दो। इसे लिए understanding हो गई है, अब MoU साइन होगा और MSME के लिए और खादी

और विलेज इंडस्ट्री के लिए हम लोग Alibaba और Amazon जैसा marketing portal ला रहे हैं, जिसमें काफी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। न्यूयार्क में बैठा हुआ आदमी अपनी कम्प्यूटर स्क्रीन पर बनारस की साड़ी देखकर उसका ऑर्डर करेगा और उसको वहां डिलिवरी मिल जाएगी। निश्चित रूप से इसमें जो 25% रिज़र्वेशन है, उसमें से 3% रिज़र्वेशन महिलाओं को मिलेगा। Technology access का भी काफी काम हुआ है। अब आप एक चीज़ देखिए, MSME Sector में there are challenges. There are problems but, as always, I am of the opinion that there are some people who convert problems into opportunities and there are some who convert opportunities into problems. Our Government wants to convert problems into opportunities. इसमें मुझे प्रॉब्लम्स हैं, चैलेन्जेज़ हैं। शुरुआत में टीथिंग ट्रबल, स्टार्टिंग ट्रबल होती ही है। मुझे लगता है कि आप सबसे सहयोग से इसमें से बाहर निकल कर आगे जाएंगे। एक्सपेन्शन ऑफ टेक्नोलॉजी सेन्टर्स 2018-2019 में 18 थे और अभी 35 होंगे, इनको 153 बनाने का टारगेट 2023-2024 तक किया है। क्रेडिट गारंटी सपोर्ट अंडर स्कीम में एक करोड़ के लगभग 2018-2019 में थे, इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, इस साल यह 45 से 50 हजार करोड़ है, हमने इसे एक लाख करोड़ तक करने का टारगेट बनाया है। हमने ये टारगेट्स रखे हैं। Target is not the part of commitment. मैं पहले एनएचएआई में था तो मैं कहता था कि हम लोग 40 किलोमीटर पर डे बनायेंगे तो मुझसे सवाल पूछते थे कि क्या 40 किलोमीटर पर डे बने? मैंने कहा कि जब आपका लड़का एग्जाम में बैठता है तो आप उसे बोलते हैं कि मेरिट में पास हो, वह मेरिट में पास हो, यह उसका टारगेट है। यह कोई ऐसा नहीं है, उसे मेरिट बोलने के बाद वह फर्स्ट क्लास में पास होता है। यह जो टारगेट्स हमने रखे हैं, काफी अच्छे हैं और इनमें खादी ग्रामोद्योग से लेकर हमारे जितने स्टॉक होल्डर्स हैं, उनका सबका इसमें अंतरभाव है और इसे बढ़ाने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं।

फ्यूचर इनिशिएटिव्ज़ में जो यू.के. सिन्हा कमेटी की रिपोर्ट्स आई थीं, उनकी रिक्मण्डेशंस में 39 रिक्मण्डेशंस, यह रिजर्व बैंक ने कमेटी अपॉइन्ट की थी और इसे भारत सरकार ने स्वीकार किया है। The MSME Fund of Funds is of ₹ 10,000 crore. The proposal is approved by the Finance Ministry. Now we will take it to the Cabinet for its approval. Distressed Asset Fund is of ₹10,000 crore. The proposal is approved by the Finance Ministry. Now we will take it to the Cabinet for its approval. The RBI has issued a circular extending the time for one-time restructuring of stressed accounts till 31.12.2020 and over six lakh accounts have already been restructured by banks. इसकी मुद्दत अब 31 दिसम्बर तक बढ़ाई गई है। Five hundred Enterprise Development Centres to provide handholding support to entrepreneurs. एडीबी, वर्ल्ड बैंक ने हमें फंड दिया है। करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये एडीबी और साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक, एक हजार करोड़ रुपये केएफडब्ल्यू, ये क्रेडिट लाइन सस्ते में मिलेगी। उन्होंने भी अप्रूव किया

[श्री नितिन जयराम गडकरी]

है। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेन्टर्स सौ होंगे, ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेन्स सिस्टम एमएसएमई में एक्सपोर्ट के लिए होगी। एमएसएमई गेटवे का मैंने आपको बताया कि हम लोग अलीबाबा या उसके जैसी योजना कर रहे हैं।

एक बैंक ऑफ आइडियाज़ इन्नोवेशन एंड रिसर्च, इसको शुरू करने के लिए मैं इसका उद्घाटन करूंगा। हमें आप टेक्नोलॉजी वगैरह के आइडियाज़ दो, हम उसको सपोर्ट करेंगे। स्टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यह कन्करेन्ट लिस्ट में हैं। स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग के बिना हम नहीं कर सकते। अब स्टेट गवर्नमेंट की भी रैंकिंग सिस्टम 4 Es किया है। एमएमएमई में कौन सी राज्य सरकार ने अच्छा काम किया, उसका हर साल ऑडिट होगा। एन्टरप्राइज क्रिएशन, इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन, एक्सपोर्ट्र एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, लाइसेन्स राज को खत्म करना - इन चार बातों पर हर स्टेट का मूल्यांकन होगा और परफार्मेन्स ऑडिट होगा और उसकी रेटिंग होगी, रैंकिंग मिलेगी, तो मुझे लगता है कि इसमें काफी सुधार आएगा।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Mantri ji, are you going to conclude?

**श्री नितिन जयराम गडकरी:** मैं दो मिनट में खत्म करता हूं। कॉयर के बारे में जो साउथ इंडिया से रिलेटेड लोग हैं, इसमें कॉयर को रोड में विशेष रूप से जो हमारा जियो फैब्रिक है, कॉयर जियो फैब्रिक, यह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना...**(व्यवधान)**...

SHRI VAIKO: Tamil Nadu.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Yes, I know the problem. From the core of my heart, I want to support the people hundred per cent who are already involved in this business. The situation is not good. मैंने एनएचएआई को कहा, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को कहा कि कॉयर का जियो फैब्रिक डालने से रोड की लाइफ बढ़ती है। आपको पता ही है तो एनएचएआई ने कहा कि टेक्निकली प्रूव नहीं हुआ। कल ही मीटिंग हुई, मैं नहीं जा पाया। चेन्नई आईआईटी को हमने अपॉइन्ट किया है। रोड कन्सट्रक्शन में, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इम्बार्कमेंट और उसके साथ-साथ बाकी सब बातों के लिए इसका उपयोग करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत आवश्यक है।

सोलर चरखा, इसके लिए मैंने कहा कि आप एक बार सोलर चरखा देख लीजिए। कभी मौका लगा तो मैं यहां भी लाऊंगा। इतनी सुंदर योजना है कि दस लाख महिलाओं को पांच साल में सोलर चरखे बांटेंगे तो एक महिला की इनकम 18 से 20 हजार रुपये महीना होगी। यह योजना भी ली है। अच्छी बात यह है कि मैंने अपने विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी को

कहा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ बैठकर आप बात करो कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट इकोनॉमी क्या होगी? जो-जो आयात हो रहा है, वह एमएसएमई में क्या हो सकता है? आपको बताते हुए मुझे अभिमान होता है कि चरखे से लेकर चंद्रयान तक पूरा एमएसएमई है। चंद्रयान पर जो गया, उसमें भी पोर्ट्स एमएसएमई में बनाये हैं। अब स्वाभाविक रूप से इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट पर हम काम कर रहे हैं और उसमें भी जल्दी काम होगा। मैंने hydroponics की बात की, मैंने bamboo की बात की, rural, agriculture and tribal और 115 Aspirational Districts के लिए हम लोग अलग से यह काम करेंगे।

इसके साथ-साथ मैं फिर से एक बार आप सब को बहुत धन्यवाद देता हूं। बताने लायक तो बहुत सी चीज़ें हैं। कोई बजट कट नहीं हुआ है। मैं आपके भाषणों में से सबको सुझाव देता हूं। कई योजनाएं हमने बंद कर दीं, कोई योजना दूसरी योजना में मर्ज कर दी, इसके कारण वह पैसा कम दिखता है। हमने अपना corpus fund काफी बना लिया, तो पैसे की पोजिशन कम की, क्योंकि जरूरत नहीं थी, इसलिए कोई कट नहीं हुआ है। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह हमारी backbone है, यह हमारी रीढ़ की हड्डी है और इसके भरोसे आगे का देश खड़ा होगा। हमारी जो five-trillion dollar economy होने वाली है, उस economy में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलन बने, गांव से रोजगार मांगने के लिए कोई शहर में न आये, गांवों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार निर्माण हो, handloom, handicrafts को प्रोत्साहन मिले, export बढ़े, per capita income, GDP और growth rate बढ़े, गरीबी दूर हो। हमारे देश की जो economy है, उसे five-trillion dollar की economy बनाने का जो प्रधान मंत्री जी का सपना है, उसमें MSME 100 per cent अच्छी तरह से contribute करेगी। इसी विश्वास के साथ आप सब को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Prof. Jha. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, textile...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): One minute. I have called Prof. Manoj Jha. I will call you next for seeking a clarification.

**प्रो. मनोज कुमार झा** (बिहार): माननीय मंत्री जी, 16 मार्च को मैंने एक प्रश्न पूछा था। मुझे बेहद अच्छा लगा कि आपने कहा कि राज्यों का मूल्यांकन आप चार आधारों पर कर रहे हैं। मैंने बिहार के target और achievement दोनों देखे। वह चिंता का विषय है। उस संदर्भ में अगर आप एक बार कुछ बतायें, तो बेहतर होगा।

**श्री नितिन जयराम गडकरी**: उपसभाध्यक्ष महोदय, सब्जेक्ट तो केवल भारत सरकार से सम्बन्धित नहीं है। राज्य सरकार को cooperate करना, facilitator के रूप में मदद करना,

[श्री नितिन जयराम गडकरी]

यह हमारा काम है। जो District Industries Centres हैं, उनका भी स्वरूप बदलने का निर्णय किया गया है। हम लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, लोन मंजूर करने के लिए तैयार हैं। अब यह बात कहना मेरे लिए ठीक नहीं है कि पहले हम कहते थे कि योजना स्टेट गवर्नमेंट के District Industries Officer को आप apply करो, परन्तु हमारे पास application ही नहीं आती थी, फिर मैंने तय किया कि इसको हटा दो, अब direct apply कर दो, हम निर्णय करेंगे। तो naturally यही है कि उनके साथ हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करेंगे और राज्य सरकार की हम पूरी मदद करेंगे और उसको बढ़ायेंगे।

आपने एक important चीज़ कही कि अभी यह जो कोरोनावायरस चल रहा है, सब बंद है। कल रात में मैं एक होटल में खाना खाने के लिए गया था, तो पूरा होटल खाली पड़ा था। ये MSMEs हैं, छोटे-छोटे उद्योग हैं। Industry में गड़बड़ी है। काफी काम stop हुआ है। टेक्सटाइल की भी प्रॉब्लम है। कल शाम को फाइनेंस मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई है। मैंने अपनी तरफ से कुछ रिकमंडेशंस भेजे हैं, परन्तु उनके बारे में आज यहां कुछ बताना उचित नहीं होगा। आपकी कही हुई बात legitimate and genuine है। मैं अपनी तरफ से यह जो संकट है, इसमें MSME पर भी बहुत बड़ा संकट है। उनको जो installment देना है, ब्याज लग रहा है, परिस्थिति ऐसी है कि मार्केट एकदम डाउन हो गयी है, तो क्या इसमें कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ रिकमंडेशंस मेरे विभाग ने वित्त मंत्री जी को दिये हैं। अंतिम निर्णय वे करेंगे। मैं जरूर कोशिश करूंगा। I know the problem.

**श्री आनन्द शर्मा** (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मंत्री महोदय ने बड़े विस्तार से बताया, जितना मैंने सुना। मैंने पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन जितनी सुनी... पूरा सदन काफी प्रभावित है। इनकी बात सुन कर लगता है कि कोई भी चुनौती अभी नहीं है, हरेक काम ठीक चल रहा है। आपको शुभकामनाएं। आपसे उम्मीद भी है। ये बड़े डायनामिक मंत्री हैं। जो भी विभाग आप देखते हैं- मैं तो आपकी बात सुन कर सोच रहा था कि सरकार को और देश में जितनी चिन्ताएं हैं, अगर सूचना और प्रसारण भी आप ही देखते तो सब चीज़ें अच्छी लगतीं।

खैर, यह कहने के बाद, मुझे माननीय मंत्री महोदय से एक बात पूछनी है। पहले आपने innovation की बात कही। MSME Sector, जहां से देश का जो उत्पादन होता है, उद्योग का 40 प्रतिशत होता है और 45 प्रतिशत हमारा जो export है, वह MSME Sector से जाता है। एक तो innovation के लिए आपने क्या कोई separate fund उसमें बनाया है? आपने उसका जिक्र किया था। दूसरा, cost of credit क्या है? आपने इसका उल्लेख किया। बैंकों के पास इतना पैसा है, कोऑपरेटिव बैंक के पास, दूसरे एनबीएफसीज़ के पास इतना पैसा है, एनबीएफसीज़ के पास कई चुनौतियां भी हैं, बैंकों के पास भी एनपीएज़ की समस्या है,

पर उनके पास कितना पैसा उपलब्ध है, cost of credit क्या है? हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या cost of credit की है। क्या आप एमएसएमई के लिए कोई interest subvention दे रहे हैं?

तीसरा, आपने अभी जिस बात का उल्लेख किया और सांकेतिक भाषा में तो कहा कि आप चिंतित हैं कि अभी विश्व के सामने जो संकट आया है, यह वैश्विक संकट है, उसमें खास तौर पर जिन लोगों का रोजगार जाएगा, जो छोटे उद्योग में हैं, लघु उद्योग में हैं, जो बंद हो गए हैं, उनके लिए आप क्या प्रावधान करेंगे? विश्व में कई सरकारों ने यह किया है। अभी कुछ महीने के लिए जिनका रोजगार खत्म होगा, जब तक हम संकट से उबर नहीं जाते हैं, उनके लिए, खास तौर से लघु उद्योग के लिए आप क्या सोच रहे हैं?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Thank you Anandji. न, I would just take very quick clarificationary questions and just answer everyone in one shot.

**श्री नितिन जयराम गडकरी**: उपसभाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं भूल जाऊंगा, इसलिए पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Okay.

**श्री नितिन जयराम गडकरी**: उपसभाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो ऐसी है कि logistic cost, capital cost and production cost, इनका संबंध export के साथ है और यह सच्चाई है कि हमारे यहां bank interest बहुत ज्यादा है। इसके लिए हम 2 per cent subsidy देते हैं यानी अगर 11 per cent लगा, तो 9 per cent लगता है और इसके लिए हमने 625 करोड़ रुपए disburse किया है, पर, इसके लिए 9 per cent भी ज्यादा है।

**श्री आनन्द शर्मा**: इसको कम करना चाहिए।

**श्री नितिन जयराम गडकरी**: यह मेरे हाथ में नहीं है। हमने इसमें तीन credit line लिए हैं, एक World Bank की, एक ADB की और एक KFW की है और ये तीनों मिला कर करीब सात हजार करोड़ हैं। इसको शायद हम लोग 6-7 परसेंट तक ला पाएंगे। Interest cost कम करना मेरे हाथ में नहीं है, पर वर्ल्ड में देखा जाए, तो जापान में interest cost वन परसेंट है और चीन में भी interest cost बहुत कम है। हमारी capital में interest cost बहुत ज्यादा होती है। हम इसके लिए कोशिश करेंगे।

दूसरी बात यह है कि यह जो कोराना की बात आई है, इससे कहीं न कहीं नुकसान हुआ है, क्योंकि यह natural calamity है। मैंने अभी सम्माननीय सदस्य के जवाब में कहा कि कल Finance Minister ने meeting बुलाई है, मैंने अपनी तरफ उनको कुछ proposals

[श्री नितिन जयराम गडकरी]

दिए हैं, पर आज उनके बारे में कहना उचित नहीं होगा। Finance Minister उन पर निर्णय करेंगी।

Innovation के लिए already योजनाएं हैं और हम पैसे भी दे रहे हैं हैं। Innovation करने वाले, startup करने वालों के लिए हम स्पेशल एक करोड़ रुपए तक तुरंत देते हैं। हम इस तरह से उनकी मदद करते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Please keep the interventions to one sentence and, similarly, the Minister.

**श्री रवि प्रकाश वर्मा:** सर, जिले के स्तर पर जो DLRC बैठती है, MSME के जो भी provisions हैं, उनको incorporate करने के लिए, लोगों को advise करने के लिए, एक financial adviser के तौर पर काम करने के लिए। क्या उसमें banking के माध्यम से कोई अच्छा provision करा देंगे? अगर यह करा देंगे, तो हम लोगों के लिए बहुत आसान होगा।

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, due to time constraints, I cut short. Everybody appreciates your intentions and the goodwill and your dynamism. There is no doubt about it but the way in which you approached the impact of the demonetization and the GST, is still doubtful. So, I would request you, whether the Government publish a white paper on the impact of the demonetization and GST on the MSME in the coming three months' time.

DR. BANDA PRAKASH (Telangana) : Sir, the Government is announcing the cluster approach into the MSMEs. The Telangana Government is also doing the same. They are going forward on the cluster approach. What are the facilities and support that you would give for the cluster approach and linkages with the big industries? Thank you.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, can you advise the nationalized banks as because of the Coronavirus problem the people are staying at home? They are not in a position to repay their mortgaged loans. At least, defer the recovery or defer the application of penal interest on the EMIs. Can you tell about that?

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister one thing. As he knows, Bengaluru has got one of the biggest public sectors units. One of the major units is ITI, that is, Indian Telephone Industries.

It was the biggest in Asia. It has closed down. Many of the public sectors have closed down. It had huge ancillaries. Do you have any plans for re-development of those ancillary units in Bengaluru?

**श्रीमती रूपा गांगुली** (नाम निर्देशित): सर, जिस तरह से खादी ग्रोमोद्योग पर आपने इतना ध्यान दिया है, वैसे ही electrical, mining और machinery पर लोगों को और थोड़ी मदद चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Now the last clarification; Dr. Amee Yajnik.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Mr. Minister, all the steps that you mentioned and all the schemes also are laudable. I only wish to ask one pointed question. How are you going to solve the liquidity crunch, the liquid money which is not available to these people at the micro level, not medium or small? How will you tell or how will you walk the extra mile to see that the banking sector makes these funds available to this micro sector? My one pointed question is this.

The second question is this. How will you make these micro-level people understand that these are the schemes or make them aware of all this knowledge or technological innovations involved in all these setups that you are talking about?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Now, Mr. Minister.

**श्री नितिन जयराम गडकरी**: सम्माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो लोग ऑलरेडी debt trap में फंसे हुए हैं... यू.के. सिन्हा समिति ने 39 रिकमंडेशंस दिए हैं और 103 निर्णयों के लिए कहा है कि ये करने हैं। इसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट involved हैं और उनका बार-बार रिव्यू करते हैं। मैं समय के कारण आपको डिटेल में नहीं बता पाया, लेकिन यू.के. सिन्हा कमिटी में आपकी लगभग सब समस्याओं के जवाब हैं। यू.के. सिन्हा कमिटी के ये रिकमंडेशंस ही फ्यूचर की पॉलिसी है। जो लोग बैंक में फंसे हुए हैं, उन पर ध्यान दिया जा रहा है। पहली बात तो मैंने आपको बताई कि छः लाख एमएसएमई का restructure हो गया है। इसके बाद यह मुद्दत 31 मार्च को खत्म होनी थी, लेकिन अब इसे हमने 31 दिसंबर तक आगे बढ़ाया है। यह प्रोविजन छोटे-छोटे लोगों के लिए ही है। ये जितने होंगे, उनको monitoring भी मिलेगी, restructuring भी होगी।

सर, कुछ लोगों का कर्ज का बोझ ज्यादा है, उनके लिए हमने 10,000 करोड़ का प्रोविजन किया है, ताकि ऐसे लोगों को खड़ा करने में मदद की जा सके और वे फिर से आ सकें। जो कोरोनावायरस की बात की गई, उसके बारे में जो आप सबकी भावना है, वही मेरी

[श्री नितिन जयराम गडकरी]

**5.00 P.M.**

भी भावना है। आज मैंने अपनी तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर को रिकमंडेशंस भेजे हैं। इस बारे में मैंने क्या भेजा है, यह आज उनकी अनुमति के बिना बताना उचित नहीं होगा। आपकी भावना की चिंता मैं उनके सामने जरूर रखूंगा।

सर, जहां तक जीएसटी और नोटबंदी, इन दोनों विषयों की बात हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वह एक phase था। आप भी यह मानते हैं कि स्वाधीनता के बाद सबसे बड़ा economic reform जीएसटी है और इसका सब पार्टी ने सपोर्ट भी किया है। हम जब कोई नई पॉलिसी स्वीकारते हैं, जब reform होता है, तब शुरुआत के समय में प्रॉब्लम आती है, पर धीरे-धीरे परिस्थितियां काफी बदली हैं और इसमें काफी राहत मिली है। हमारे पास जैसे-जैसे सुझाव आए, उस हिसाब से हमने काफी rectification किए हैं, रेट भी कम किए गए हैं। एक्सोर्ट करने वालों की जो रिफंड की प्रॉब्लम थी, उसकी अड़चनें दूर की गई हैं। साथ ही जब भी कोई समस्या आती है, तो उस पर लगातार विचार होता है। मुझे लगता है कि यह प्रॉब्लम धीरे-धीरे काफी बड़े पैमाने पर कम हुई है। नोटबंदी के बाद एक बात जरूर सामने आई कि बहुत-से सेक्टर हमारे सिस्टम में नहीं थे, यानी हमारी भाषा में वह नंबर दो का बिजनेस था, without bill का था। मैं यह मानता हूं कि जो पैसा, जो capital employment potential खड़ा करने के लिए खर्च होता है, हमें उसे ब्लैक मनी नहीं कहना चाहिए। उसके लिए हमने नैचुरल रूप से यह कोशिश की है कि उसके बाद से उन्हें कई benefits और incentives दे रहे हैं और जीएसटी कितना बढ़ा है और आपने turnover कितना किया है, इस आधार पर बैंक तुरंत लोन दे रहे हैं। इस आधार पर उनको facility मिल रही है और इंडस्ट्रीज़ को expansion करने का मौका मिल रहा है। इन दोनों स्थितियों के बाद जो भी अड़चनें थीं, सरकार ने उन्हें सुलझाने का पूरा प्रयास किया है। अब वे normalize हो गई हैं। मैं नहीं मानता कि अब यह समस्या बहुत बड़ी है।

---

## DISCUSSION ON THE WORKING OF MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Now, we will move on to the discussion on the working of the Ministry of Law and Justice; Shri Bhupender Yadav.

**श्री भूपेन्द यादव** (राजस्थान): सम्माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपनी पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि उसने मुझे लॉ एंड जस्टिस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा प्रारंभ करने का अवसर प्रदान किया।